

न्यायिक नियुक्तियां

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का
प्रश्न पर हात के याद-विवाद का एक विद्वेपन

११

श्री १।

श्री २।

श्री ३।

द्वारा श्रीमान् सुभाषचन्द्रबोस

अगस्त १९७३ (PH 39)

कॉपीराइट १९७३ पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा) लिमिटेड,
नई दिल्ली

मूल्य

साधारण सस्करण ३ रु

सजिल्द सस्करण ७ रु

सर्वा सागुन्ता हाता गुणज प्रिन्टिंग प्रेस, रानी भागी रोड नई दिल्ली म
मुद्रित और डेही व द्वारा पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा) लिमिटेड, नई दिल्ली
को सर्व म प्रदानित ।

कोई भी उच्चतम न्यायालय और कोई न्यायपालिका समस्त जन-समुदाय की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली ससद की प्रभुपक्षापूर्ण इच्छा के विषय में निर्णय नहीं दे सकती। अगर हममें इधर-उधर कुठ गलती होनी है तो वह उसको गता सकती है, मगर अतन, जहां तक जन-समुदाय के भविष्य का प्रश्न है, कोई न्यायपालिका उसके रास्ते में नहीं आ सकती। और अगर वह रास्ते में जाती है तो आखिरकार सारा सविधान ससद की ही बन-यो हुई चीज है। किन्तु हमें न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और सारे देश के उच्च न्यायालयों का सम्मान करना चाहिए। बुद्धिमान लोगों की तरह उनका कर्तव्य यह देखना है कि किसी मावावेश के क्षण में, उत्तेजना के क्षण में, जनता के प्रतिनिधि भी गलत रास्ते पर न चले जायें, वे जा सकते हैं। न्यायालयों के एकांतिक वातावरण में, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कोई काम न हो जो सविधान के विरुद्ध हो, देश के हित के विरुद्ध हो, व्यापकतर अर्था में जन-समुदाय के विरुद्ध हो। इसलिए अगर ऐसी घटना हो जाय तो उन्हें इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहिए, मगर यह स्पष्ट है कि कोई अदालत, कोई न्याय-व्यवस्था, एक तीसरे सदन के रूप में, एक प्रकार से गलती सुधारने वाल तीसरे सदन के रूप में, काम नहीं कर सकती। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका इस सीमा के साथ काम करे।

अगर जनता को प्रभावित करने वाले जीवन्त प्रश्नों पर सरकार की नीति, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा अनुल्लघनीय रीति से निर्धारित होगी तो व्यक्तिगत कार्यवाहियों के विषय में पक्ष-विपक्ष के साधारण भ्रूदमों में जिस क्षण वे किये जायेंगे, उस समय अमल में उस सीमा तक उस सुयोग्य अदालत के हाथों अपनी सरकार सौंप कर, जनता स्वयं अपनी शासक नहीं रह जायगी ।

अब्राहम लिंकन

आम ज़ात के मरिक्का में सन्निधान की पवित्रता के परम्परागत सम्मान के साथ ऐसे लोगों के विषय में, विशेषकर वकीलों के विषय में, जो अपने लिए कभी गलत न होने का दावा करते हैं, एक अतः स्फूर्त अनिश्वास का भाव घुलमिल गया है । अमरीका के इतिहास में लगभग हर सशक्त राष्ट्रपति का रिश्ता न किसी समय अदालत से टकराव हुआ है । जब ऐसा हुआ तो उसकी आपत्तियों को जनता के प्रीति आश्चर्यजाक रूप से व्यापक समर्थन मिलते देखा गया ।

माथर इलेसिंगर, जूनियर

प्राक्कथन

यह पुस्तिका उन कारणों की व्याख्या करने के लिए लिखी गयी है जिनके वश भारत सरकार ने अप्रैल १९७३ में सबसे वरिष्ठ 'यायाधीश' को उच्चतम 'यायालय' का मुख्य 'यायाधिपति' नियुक्त करने की विध्वनी रीति त्याग दी।

उस समय के 'यायाधीश ए. एन. राय' को मुख्य 'यायाधिपति' नियुक्त किये जाने के विरुद्ध विरोध का तूफान उठ खड़ा हुआ, विशेषकर वकील सभ के मेरे सहयोगियों की ओर से। किंतु मेरा विश्वास है कि यह विरोध उन मन्तव्यों की जिनके कारण सरकार ने 'यायाधीश' राय को नियुक्त किया और साथ ही, ऐसे उच्च पद पर नियुक्तियों के प्रश्न पर जो बुनियादी आधार होने चाहिए उनकी भी समझ में कभी के कारण पैदा हुआ। इस पुस्तिका को लिखने में मेरा उद्देश्य है इन दोनों ही मामलों की उचित समझदारी के लिए सामग्री प्रस्तुत करना।

मैंने तथ्यों के उदाहरण देने में और साथ ही उनके प्रस्तुतीकरण में यथासम्भव सही बने रहने का प्रयत्न किया है। मैं वकील सभ में अपने सहयोगी और मित्र श्री राम पञ्जवानी का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे द्वारा प्रयुक्त सामग्री एकत्र करने में धनपूर्वक धन दिया और मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। किंतु यदि तक में कोई गलतियाँ या कमजोरियाँ हों तो वे मेरी, सिर्फ मेरी ही हैं।

बिस्ली

५ मार्च १९७४

एस. मोहन कुमारमगलम

प्राक्कथन

- १ सविधान की व्यवस्थाएँ
- २ उच्चतम 'यायालय'—१९६७ १९७०
- ३ २४वा और २५वा संशोधन
- ४ जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में न्यायाधीशों का संकथन
- ५ अमरीकी उच्चतम 'यायालय' और "नव व्यवहार नीति"
- ६ 'यायाधीशों का दर्शन
- ७ पदोन्नति और वरीयता
- ८ निष्पक्ष
- ९ उपसंहार

१
७
१६
२५

३६

५०

५६

६४

६६

७३

७६

७८

७९

८०

८१

परिनिष्ठ

- १ बैजामिन कार्डोजो की पुस्तक 'दि नेवर ऑफ दि जूडीशल प्रॉसि' से उद्धरण
- २ फ्रेड रोडेल की पुस्तक "लाइन मेन" से एक उद्धरण
- ३ भारत के उच्चतम 'यायालय' के मुख्य 'यायाधिपतियों की सूची' (१९५० १९७३)
- ४ अमरीका के उच्चतम 'यायालय' के मुख्य 'यायाधिपतियों की सूची' (१८०१ १९७३)
- ५ इंग्लैंड के मुख्य 'यायाधिपतियों की सूची' (१९०१ १९७३)
- ६ कनाडा के उच्चतम 'यायालय' के मुख्य 'यायाधिपतियों की सूची' (१९०० १९७३)
- ७ आस्ट्रेलिया के उच्च 'यायालय' के मुख्य 'यायाधिपतियों की सूची' (१९०३ १९७३)

१. संविधान की व्यवस्थाएँ

भारतीय संविधान के अनुसार, मुख्य 'यायाधिपति' समेत उच्चतम 'यायालय' के सभी 'यायाधीश' की नियुक्तियाँ, संविधान की धारा १२४ के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। अनुच्छेद १२४ में व्यवस्था है

- (१) भारत का एक उच्चतम 'यायालय' होगा जो भारत का मुख्य 'यायाधिपति' तथा, जब तक संसद विधि द्वारा और अधिक गण्य विहित नहीं करती तब तक, अन्य ७ से अधिक 'यायाधीश'ों में मिल कर बना।
 - (२) उच्चतम 'यायालय' के, तथा राज्यों के उच्च 'यायालय'ों के ऐसे 'यायाधीश'ों से परामर्श करके, जिनसे निम्न प्रमाणन के लिए परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के साथ तथा वह 'यायाधीश' तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह ६५ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले।
- परंतु मुख्य 'यायाधिपति' में निम्न शर्तों का प्रयोग किया जा सकता है—
 (क) यदि 'यायाधीश' राष्ट्रपति का सम्बन्धित ११वें अनुच्छेद १२४ के अन्तर्गत

लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा,

(ख) सड़ (४) में उपबोधित रीति में कोई 'यायाधीश अपने पद से हटाया जा सकेगा।

(३) उच्चतम 'यायालय के 'यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब तक जहाँ न होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो तथा—

(क) किसी उच्च 'यायालय का अध्यक्ष ऐसे दो या अधिक 'यायालयों का लगातार कम से कम ५ वर्ष तक 'यायाधीश न रह चुका हो, अथवा

(ख) किसी उच्च 'यायालय का, अध्यक्ष ऐसे दो या अधिक 'यायालयों का, लगातार कम से कम १० वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो, अथवा

(ग) राष्ट्रपति की राय में पारगट त्रिधिवक्ता न हो।

स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद के अनुसार, जहाँ नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है यानी मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य कर रहा राष्ट्रपति को है, वहाँ राष्ट्रपति को छूट है कि सभी नियुक्तियों के विषय में उच्च 'यायालय या उच्चतम 'यायालय के किसी 'यायाधीश से सलाह ले, भगवत् उच्चतम 'यायालय के 'यायाधीश की नियुक्तियों के मामले में उन पर भारत के मुख्य 'यायाधिपति की सलाह लेने का शासनादिकृत कर्तव्य डाला गया है।

किंतु धारा १२४ की व्यवस्था का यह भी निहित अर्थ है कि यह शासनादिकृत कर्तव्य सिर्फ उच्चतम 'यायालय के 'यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में है और यह जिम्मेदारी नहीं डाली गयी है कि जब किसी नये मुख्य 'यायाधिपति की नियुक्ति का प्रश्न हो तब अवकाश प्राप्त करने वाले मुख्य 'यायाधिपति से सलाह ली जाय। यह मामला जब हम अनुच्छेद १२६ की परीक्षा कर रहे हैं तो और अधिक स्पष्ट हो जाता है।

जब भारत के मुख्य 'यायाधिपति का पद रिक्त हो अथवा जब मुख्य 'यायाधिपति अनुपस्थिति या अन्य कारण से, अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तब 'यायालय के अन्य 'यायाधीशों में से एक को जिस राष्ट्रपति उन प्रयोजनों के लिए नियुक्त कर उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

इस प्रकार जब कार्यकारी मुख्य 'यायाधिपति की नियुक्ति के मामले में न्याय विधि के आधार पर नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है तब म्यासी मुख्य 'यायाधि

पनि की नियुक्त के मामले में तो यह बात और भी अधिक सच बैठती है। अनुच्छेद १२६ त्रिकुल स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जहाँ तक राष्ट्रपति की मर्जी का सवाल है, वह सिर्फ उच्चतम 'यायालय' के 'यायाधीश' तक ही सीमित है मगर वह 'यायाधीश' में से ही किसी को चुन सकते हैं और पदासीन 'यायाधीश' में से अत्यन्त जूनियर तक को नियुक्त करने में उनके लिए कोई रखावट नहीं है। इसलिए जहाँ तक संविधान के अनुसार अधिकार का प्रश्न है, स्थिति निर्विवाद है। अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, उनको छूट है कि कोई भी नियुक्ति करने में उसके मामले में वह किसी भी उच्च 'यायालय' या उच्चतम 'यायालय' के किन्हीं 'यायाधीश' से सलाह ले, जहाँ तक 'यायाधीशों' की नियुक्ति का प्रश्न है उन्हें मुख्य 'यायाधिपति' से सलाह लेनी चाहिए, मगर जहाँ तक मुख्य 'यायाधिपति' की नियुक्ति का प्रश्न है उन पर किसी से भी सलाह लेने का दायित्व नहीं डाला गया है।

फिर भी यह सच है कि पिछले वर्षों में अमल के रूप में उच्चतम 'यायालय' के मुख्य 'यायाधिपति' के बाद के सीनियर 'यायाधीश' को मुख्य 'यायाधिपति' का उत्तराधिकारी बनाया जाता रहा है।

एक मात्र आपवाद था 'यायाधीश' इमाम का, जिन्हें अपने खराब स्वास्थ्य के कारण और स्पष्टतः 'यायालय' की अध्यक्षता के मामले में असमर्थ होने के कारण उन्हें उच्च पद नहीं दिया गया, और इसलिए 'यायाधीश' गजेन्द्रगढ़कर को मुख्य 'न्यायाधिपति' नियुक्त किया गया। इस प्रकार सारी स्थिति का सार यह निष्कर्ष है

- (१) संविधान के सम्बंधित अनुच्छेद की व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति के नियुक्ति अधिकार की कोई सीमाएँ नहीं निश्चित की गयी।
- (२) अनेक वर्षों से अमल यह रहा है कि अगले सीनियर 'न्यायाधीश' को नियुक्त कर दिया जाता था।

क्या वह अमल जारी रखना चाहिए और इस परम्परा को लगभग एक अपरिवर्तनशील नियम बना देना चाहिए—इस वष सरकार के सामने यही प्रश्न उपस्थित था।

यही पर विधि आयोग की चौहवी रिपोर्ट—'न्यायिक प्रशासन पर उसकी रिपोर्ट'—प्रासंगिक बन जाती है। आयोग में आज के कुछ अत्यधिक विख्यात कानूनी और 'न्यायिक' नेता शामिल थे। उसमें उस समय के एटर्नी-जनरल एम सी सोतलवाड़, जिनके कानूनी कार्यालय ने उनको चालिस वर्ष से अधिक समय से कालत के उच्चतम क्षेत्र में बनाए रखा है, की अध्यक्षता

बम्बई के उच्च न्यायालय में उस समय के मुख्य न्यायाधीपति एम. सी. दामोदा, राजस्थान उच्च न्यायालय में उस समय के मुख्य न्यायाधीपति जी. रा. दाद म उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति के एक वाचु पत्र में उस समय के एडवोकेट जनरल और बाद में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति एस. एम. मोकरी, भारत के वर्तमान उप राष्ट्रपति जी. एस. पाठक और उच्चतम न्यायालय के एक सीनियर एडवोकेट एन. ए. पाठक की जड़ विख्यात व्यक्ति सम्मिलित थे।

विधि आयोग को सबसे बरिष्ठ न्यायाधीश को पदोन्नति दिए जाने के अमल की पूरी जानकारी थी और इसलिए उन्होंने इस मामले में अपने "बिना पूर्ण विचार" शब्द का प्रयोग किया।

उन्होंने अपने विचार निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किए^१

जब तक पद रिक्त होने पर बरिष्ठतम अनुवर्ती न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीपति के लिए पदानुगत करने की प्रथा चली आयी है। ऐसा लगता है कि ऐसी पदोन्नति एक अमली नीति बन गयी है। भारत के मुख्य न्यायाधीपति को जैसे उच्च और महत्वपूर्ण दायित्व पूरे करने होते हैं उनमें हम चर्चा कर चुके हैं। स्पष्ट है कि ऐसी प्रवृत्ति के पद के उत्तराधिकार को मात्र बरिष्ठता द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीपति के दायित्व पूरे करने के लिए न सिर्फ न्याय और अनुभववान न्यायाधीश की आवश्यकता है, बल्कि एक ऐसे क्षमतावान प्रशासक की भी जो समय-समय पर पैदा होने वाले जटिल प्रश्नों का मुनभाने में समर्थ हो जन-साधारण और विशिष्ट व्यक्तियों का चतुर परीक्षण करे और सर्वोपरि, गृह स्वतंत्रता तथा महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो जो समय पड़ने पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का रक्षक भी बन सके। यह सचमात्र है कि एक सफल मुख्य न्यायाधीपति के लिए जिस विशेष गुणा की आवश्यकता होती है, वही नीति का प्रतिभासम्पन्न और न्याय न्यायाधीश बनने वाले विशेष गुणा में भिन्न होते हैं। इसलिए हमें पद के लिए ध्यान देना है कि निम्नलिखित गुणाओं का ध्यान रखना आवश्यक है व उनसे भूत भिन्न हानी चाहिए जिसमें उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्धारित की जाती है। अब हमारी राय में, भारत के मुख्य न्यायाधीपति के लिए पद की पूर्ति करने के प्रश्न को उन विशेषताओं का सर्वोपरि ध्यान रखकर हल किया जाना चाहिए जिससे हम ऊपर उल्लेख

कर चुक है। सम्भव है कि वरिष्ठतम अनुवर्ती न्यायाधीश इन आवश्यकताओं को पूरा करता हो। अगर ऐसा हो तो उसको इस पद की पूर्ति के लिए नियुक्त किया जाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मगर बहुधा ऐसा नहीं होगा। इसलिए यह स्वस्थ परम्परा डालना आवश्यक है कि मुख्य न्यायाधिपति के पद की नियुक्ति किही विशेष विचारा पर आधारित हो और यह पद प्रयानुसार वरिष्ठतम अनुवर्ती न्यायाधीश को ही न दिया जाय। अगर ऐसी परम्परा स्थापित हो जाती है तब यदि वरिष्ठतम अनुवर्ती न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधिपति के पद पर नियुक्त नहीं किया जायगा तो उसको उस न्यायाधीश पर कोई कलक नहीं माना जायगा। हम जयन्त सुभाष दे रहे हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के मामले में ऐसी ही परम्परा डाली जाय। एक बार जब यह परम्परा स्थापित हो जायगी, तब नियुक्तियों के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनका कर्तव्य होगा कि वे उस उच्च पद के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को, अगर आवश्यक हो तो न्यायालय के बाहर के व्यक्तियों में से चुनें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधियों, वकालतखाने के विख्यात वरिष्ठ सदस्यों में नियुक्ति का विस्तृत क्षेत्र मिल सकता है।

इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि संविधान की व्यवस्था के अतिरिक्त, सामाजिक नीति का भी तकाजा है कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के अधिकार का उपयोग करने में सरकार को उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से और बाहरी व्यक्तियों में सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति को इस उच्च पद के लिए चुनना चाहिए और नियम के रूप में वरिष्ठता के आधार पर पदानुक्ति के सिद्धांत का पालन नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित यह सब है कि विधि आयोग की सिफारिशों बहुत पहले १९५६ में प्रस्तावित हुई थी और इन १४ वर्षों में वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति के सिद्धांत में हल्के का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। लेकिन यह कोई सारभूत महत्व की बात नहीं हो सकती क्योंकि जो रीति एक दशक से चली आयी थी और जिसको उस समय विधि आयोग ने त्रुटिपूर्ण तथा गलत माना था, वह सिर्फ इसलिए सही नहीं बन जानी कि उसका एक और दशक तक पालन किया गया।

वर्तमान में न केवल इन कारणों से जो विधि आयोग ने दिया है बल्कि कुछ अन्य तथा और भी वजनदार कारणों से भी निश्चय ही समस्त तक ठास

रूप में विधि आयोग के दृष्टिकोण के पक्ष में जाना है। किसी देश के मुख्य 'यायाधिपति' का पद किसी व्यक्ति को अपनी नियुक्ति की तारीख के बल पर अवकाश प्राप्त करने वाले मुख्य 'यायाधिपति' के बाद सर्वाधिक वरिष्ठ हान की आकस्मिक घटना के कारण नहीं मिल सकता। निश्चय ही जब किसी उम्मीदवार को देश के सर्वोच्च 'यायिक' पद पर बैठन के लिए चुना जाएगा तब उसके दिल और दिमाग की ओर अधिक विशेषताया, एक ओर 'यायालय' का नेतृत्व करने की सामर्थ्य तथा दूसरी ओर जनता की इच्छा-आकांक्षा का समझन की क्षमता, और इन सब का ध्यान रखते हुए जागिर बानून सन्निधान, की ध्याय्या करने की योग्यता का ध्यान रखना पड़ेगा।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे देश की स्थिति की ठोस परिस्थितियाँ में 'यायालय' को नेतृत्व प्रदान करने की मुख्य 'यायाधिपति' की क्षमता, एक नए समाज के निर्माण के लिए आग बडन के अभियान में देश की सहायता करने के कठिन कर्तव्य का पालन करा में 'यायालय' का नेतृत्व करने की सामर्थ्य।

इसमें कोई सन्देह नहीं है। सबता कि एक ओर 'यायालय' तथा दूसरी ओर मसद के बीच सम्बन्ध पिछले छे वर्षों से अधिक सुखद नहीं रहा है। और यह जीवन आवश्यकता है कि यह सम्बन्ध एक स्थायी और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हो जो भारतीय संविधान को क्रियान्वित करने वाली इन दोनों संस्थाओं की भूमिकाओं की समझदारी और उनके बीच पारस्परिक सम्मान पर आधारित हो।

२. उच्चतम न्यायालय— १९६७-१९७०

इसलिए अब यहाँ परीक्षा करना आवश्यक है कि विगत छै वर्षों में न्यायालय में क्या कुछ घटित हुआ है और अगर सविधान की इन उच्च न्यायालय में उचित तथा स्थायी सम्बन्ध स्थापित किये जाने हैं तो हमें आगामी बाल में न्यायालय में किस प्रकार का नेतृत्व उपलब्ध करना चाहिए। केवल इसी प्रकार अपने देश के उच्चतम न्यायिक पद की नियुक्ति के मामले में सही नियम तब पहुँचने के लिए उचित पृष्ठभूमि उपलब्ध हो सकती है।

पिछले छै वर्षों के, न्यायपालिका और संसद के बीच लगभग टकराव के और कानून के मामलों में मतभेद तथा अनिश्चितता के दुर्भाग्यपूर्ण वर्षों के, अनुभव को समझा जाना चाहिए और उससे सही निष्पत्ति निकाले जाने चाहिए। न सिर्फ यह कि उच्चतम न्यायालय न सरकार या संसद के दृष्टिकोण के विरुद्ध स्थितियाँ अपनायी बल्कि इससे अधिक यह कि न्यायालय न सारी कानून व्यवस्था का और विशेषतः संवैधानिक कानून का, स्वयं अपने फैसलों का लगातार पट्टा बना अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया।

उच्चतम न्यायालय में यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति वास्तव में गालबनाथ मुकदमे^१

१ १९६७ (२) उच्चतम न्यायालय अधिनियम ७६२

स प्रारम्भ होती है। उस मुकदमे में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या ससद के सविधान के भाग ३ वा, यानी जिस भाग में मूल अधिकार हैं, ससोधन करने का हक है या नहीं। मूल अधिकारों में ससोधन करने के ससद के अधिकार का दा पिछले मुकदमा में चुनौती दी जा चुकी थी, पहले, १९५२ में ससरी प्रसाद के मुकदमा में, जब उस समय के मुख्य न्यायाधिपति हरिलाल बनिया की प्रधानता में एक बेंच न, जिसमें एक विद्वान न्यायाधीश शामिल थे (उनमें से तीन बाद में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति बन) एक मत में इस विचार को सही माना कि सविधान में ससोधन करने के ससद के अधिकार-क्षेत्र में मूल अधिकारों समान प्रत्यक्ष अनुच्छेद आता है वगैरे कि जो काय विधि निर्धारित की गयी है उसका पालन किया जाय।

इसके बाद यह मामला एक बार फिर उच्चतम न्यायालय में १९६५ में सज्जन सिंह के मुकदमे में उठा जब मुख्य न्यायाधिपतिश्री में एक अत्यंत सम्मानित मुख्य न्यायाधिपतिश्री डा पी वी गजेन्द्रगटकर की अध्यक्षता में एक बेंच ने दा के मुकाबले तीन के बहुमत से ससरी प्रसाद के मुकदमा के फैसले की पुन पुष्टि की।

सज्जन सिंह के जोर साथ ही ससरी प्रसाद के, मुकदमा का फैसला इस आधार पर किया गया था कि सविधान का ससोधन करने सम्बन्धी ससद का अधिकार सविधान के अनुच्छेद ३६८ में है। इस अनुच्छेद का पाठ उस समय जैसा था, निम्नलिखित था

सविधान का ससोधन

३६८ इस सविधान के ससोधन का मूलपात उस प्रयोजन के लिए विधेयक को ससद के किसी सदन में पुरस्थापित करके ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित जोर मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अगून बहुमत से वह विधेयक पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए रखा जायगा तथा विधेयक का ऐसी अनुमति दी जान के पश्चात विधेयक के निबधना के अनुसार सविधान ससोधित हा जायगा

परंतु यदि ऐसा कोई ससोधन—

(क) अनुच्छेद ५४, अनुच्छेद ५५, अनुच्छेद ७३, अनुच्छेद १६२, या अनुच्छेद २४१ में, अथवा

१ १९५२ उच्चतम न्यायालय अभिनिर्णय ८९

२ १९६५ (१) उच्चतम न्यायालय अभिनिर्णय ६३३

१३ (१) इस सविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहले भारत राज्य-भेद में सब प्रवृत्त विधिमा उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक कि व इस भाग के उपबधा से असंगत हैं ।

(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्वारा नियमित अधिकारों को छीनती या घटाने वाली हो और इस गठ के उत्पन्न न होने वाली प्रत्येक विधि उत्पन्न की मात्रा तक शून्य होगी ।

न्यायालय ने जिस तक का पक्ष लिया, वह यह था कि अनुच्छेद १३ में "विधि" शब्द में न सिर्फ माध्यामिक कानून, बल्कि सबैधानिक कानून भी शामिल है । इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि सविधान को सन्तोषित करने वाला कानून भी अनुच्छेद १३ के अर्थ के अन्तर्गत एक "विधि" (कानून) ही होगा और इसलिए अनिवार्यतः उसको इस आधार पर कि उसमें मूल अधिकारों का उत्पन्न होता है, चुनौती दी जा सकती है । मगर मूल अधिकारों में सन्तोषित करने वाला प्रत्येक कानून अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मौजूदा मूल अधिकारों का अतिक्रमण या उत्पन्न करता है । इसलिए अनिवार्यतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल अधिकारों में सन्तोषित करने वाला कोई भी सन्तोषित बंध नहीं हो सकता और इसलिए मूल अधिकार अनुच्छेद ३६ में दिये गये सन्तोषित अधिकारों के क्षेत्र से बाहर थे ।

छै "मायाधीश का यही दृष्टिकोण था जो ऊपरी तौर पर किसी हद तक असंगत लगता है । आखिरकार जिस किसी सबैधानिक सन्तोषित में भाग ३ (सविधान में मूल अधिकारों वाला भाग) में परिवर्तन की व्यवस्था होगी, वह अनिवार्यतः मूल अधिकारों से टकरायेगा । इसलिए गोलकनाथ के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से मूल अधिकारों को सदा के लिए सन्तोषित की परिधि से बाहर रख दिया गया । इससे मूल सविधान निर्माताओं ने जैसे मूल अधिकार तैयार किये थे, उनका तगभग अधुण बना दिया गया और सविधान के जनकों के उत्तराधिकारियों का उन मूल अधिकारों में सन्तोषित या परिवर्तन करने के अवसर से वंचित कर दिया गया, भले ही अनुभव यह सिद्ध करता हो कि उनमें सन्तोषित करने की आवश्यकता है ।

और यह नोट किया जाना चाहिए कि गोलकनाथ मुकदमे में पैसदा पांच के मुकाबले छ बातों से किया गया था, जो न्यायालय के पिछले दो निर्णयों के बदलने की सही ठहराने के लिए बहुत मामूली वृद्धि है ।

न्यायालय में जगती बनी कानूनी लड़ाई का के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर

लड़ी गयी।^१ जिस विषी ने भी भारतीय राजनीति का घटना चक्र पर भारीकी से निगाह डाली है, वह इनकार नहीं कर सकता कि जुलाई १९६६ में बना का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी सरकार का फैसला गत एक चौथाई शताब्दी के भारतीय राजनीतिक आर्थिक जीवन में एक विभाजक रेखा है। और जब यह फैसला लिया गया तब राष्ट्रीयकरण कानून में पिछले मालिका के लिए मुआवजा देना उच्चतम न्यायालय के उम निणय को ध्यान में रख कर किया गया था जो निणय गुजरात राज्य बनाम शान्तिनाथ मंगलदाम^२ के मुकदमे में लिया गया था।

और विवादग्रस्त प्रश्नों की समझ सभी हासिल की जा सकती है जब उस अनुच्छेद के, यानी अनुच्छेद ३१ उपबन्ध २ के इतिहास को थोड़ा पीछे जाकर देखा जाय जिसकी उस मुकदमे में व्याख्या की गयी थी।

संविधान में अनुच्छेद ३१, उपबन्ध २, मूल रूप में जैसा था, उसका पाठ निम्नलिखित है

सम्पत्ति का अनिवार्य अजन

३१ (२) कोई स्थावर और जगम सम्पत्ति जिसमें अन्तर्गत किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में या उसकी स्वामिनी किसी कम्पनी में कोई अंश भी है ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा कब्जा या अजन करने का प्राधिकार देती है, सावजनिक प्रयोजन के लिए कब्जाकृत या अर्जित तब तक नहीं की जायगी जब तक कि वह विधि कब्जाकृत या अर्जित सम्पत्ति के लिए प्रतिवर्ष का उपबन्ध न करती हो और या तो प्रतिवर्ष की राशि को नियत न कर दे या उन सिद्धांतों और रीति का उल्लेख न कर दे जिनसे प्रतिवर्ष निर्धारित होना है और दिया जाना है।

किन्तु १९५४ में उच्चतम न्यायालय ने बेला बनर्जी^३ के मुकदमे में जो फैसला दिया था, उसमें न्यायालय ने मत प्रकट किया था कि उपराक्त अनुच्छेद में जिस 'प्रतिवर्ष' (मुआवजा) शब्द की व्यवस्था की गयी है उसका अर्थ है अधिग्रहण की गयी किसी भी सम्पत्ति की पूरी बाजारी कीमत। संविधान निर्माताओं ने जब उपराक्त अनुच्छेद की रचना की थी तब उन्होंने 'प्रतिवर्ष' शब्द का अर्थ एक ऐसी रकम समझा था जो संसद की नजर में उस सम्पत्ति के लिए न्यायमग्न

१ १९७० (३) उच्चतम न्यायालय अधिनियम ५३०

२ १९६६ (३) उच्चतम न्यायालय अधिनियम ३४१

३ १९५४ उच्चतम न्यायालय अधिनियम ५५८

मे सावधिक रकम दन की गारटी सविधान के अनुच्छेद २६१ से जारी रहनी है, मगर यह मूलतः राजनीतिक प्रकृति की है जैसा कि सविधान के अनुच्छेद ३६३ में सुरक्षित है और इस गारटी का दायित्व किसी म्युनिसिपल यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता। (पृ २०८, जोर मेरा)।

इस अंश से, जहाँ मैंने उम्मान अली के मुकदमे से उद्धृत किया है स्पष्ट प्रकट होता है कि राजाआ का मायता और प्रिवी पस पान का उनका अधिकार दोना ही मूलतः राजनीतिक प्रकृति के अधिकार हैं तथा उनको "किसी म्युनिसिपल यायालय से लागू" नहीं कराया जा सकता। अगर यही सही कानूनी स्थिति थी तो यह स्पष्ट था कि मायता वापस लेने और प्रिवी पस बद करने सम्बंधी सरकार का अधिकार सारत राजनीतिक था और उसकी वैधता पर किसी यायालय में विचार नहीं किया जा सकता था।

फिर भी जब राजाआ ने मायता वापस लेने के आदेश को चुनौती दी तो यायालय ने उस्मान अली के मामले के साथ "विभेद" किया और सरकारी आदेश को रद्द कर दिया।

निश्चय ही जमली शिकायत यह नहीं है कि यायालय ने कानून जबैध किये या सरकारी आदेश रद्द किये। यायालय गोलकनाथ मुकदमे में फैसला किये जाने के पहले और बाद में इस प्रकृति के कई फैसले कर चुका था। और इस मामले में किसी भी तरह की शिकायत नहीं की जा सकती और न की गयी। गोलकनाथ, बक राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पसों के मामले में शिकायतें यथायत्न इस तथ्य से पैदा हुई कि जब सरकार यायालय के मौजूदा फैसलों के आधार पर कायपालिका की ओर से कोई आदेश जारी करती है या कानून बनाती है तो यायालय ऐसे कानून या आदेश को अपने पिछले फैसलों को उलट-मलट कर रद्द कर देता है।

गोलकनाथ मुकदमे में उसने सरकारी प्रसाद और सज्जन सिंह दोना के मुकदमा में दिये गये यायालय के फैसले रद्द कर दिये।

बक राष्ट्रीयकरण के मामले में उमन गातिलाल मंगलदास के मुकदमे के साथ 'विभेद' किया।

राजाआ के मामले में उसने उस्मान अली के मुकदमे के साथ 'विभेद' किया।

मुकदमों के इस लगातार क्रम का फल यह था कि कानून की स्थिति के विषय में पूर्णतया अनिश्चितता फैल गयी और देश का कानून ठीक ठीक क्या है

इसके विषय में अनिश्चितता होने से आधुन हानिकारक और भ्रामक कोई दूसरी बात नहीं हो सकती ।

इसके अतिरिक्त इन तीनों ही पैंगला में एक जीवन्त कानून, जो सरकार की समाजवादी नीतियाँ के समान स्थिति थे, दाव पर चढ़ाये गये । गोलकुण्डा मुग़ल में भूमि गुंथार के कानूनों की रीति का प्रदत्त था । वे एक राष्ट्रीयकरण हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था का इस प्रकार पुनर्निर्माण करने की दिशा में एक बड़ा कदम था जिसमें कि उसको हमारे देश में इजारेदारों के नियंत्रण से निकाला जा सके और निर्णायक रूप से उस सरकार के नियंत्रण और नेतृत्व में लाया जा सके । और, राजाओं की मान्यता का वापस लिया जाना पुरानी साम्राज्यवाद परस्त सामन्ती व्यवस्था के अवशेषों के उन्मूलन के लिए अनिवार्य चोट थी—साम्राज्यवाद और समानता के लिए चोट थी ।

३. २४वाँ और २५वाँ सशोधन

एक ओर कानून के बारे में यह अनिश्चितता और दूसरी ओर हमारे देश में सामाजिक रूपांतरण के माग में रखी हुई बाधाओं को हटाने की आवश्यकता के कारण संविधान में २४वें और २५वें सशोधन किये गये। इन सशोधनों से दो उद्देश्य पूरे करने के प्रयत्न किये गये

(१) यह व्यवस्था करना कि संसद का सशोधन अधिकार इतना व्यापक हो कि यह संविधान के प्रत्येक भाग और प्रत्येक अनुच्छेद में सशोधन कर सके।

(२) उसने लिए यह सम्भव बनाना कि वह सामाजिक निर्माण की मारी प्रमुख योजनाओं का हाथ में ले सके जिनके आधार पर, 'यायातया' में कानूनी लड़ाइयाँ द्वारा राके गये बिना भारतीय समाज का समाजवादी रूपांतरण उपलब्ध किया जा सके।

इसलिए इन दो सशोधनों में निम्नलिखित क्षेत्र लिये गये

अनुच्छेद ३६८ को जिसमें सशोधन सम्बन्धी अधिकार दिये गये हैं और जागे सशोधित किया गया ताकि बिना संदेह यह स्पष्ट हो जाय कि इस अधिकार के उपयोग द्वारा संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद और भाग में सशोधन किया जा सकता है। सशोधित अनुच्छेद का पाठ इस प्रकार है

संविधान का संगोपन करने की ससद की शक्ति और उनके लिए प्रावधान ३६८ (१) इस संविधान में किसी बात के होने हुए भी ससद अपनी संविधानी शक्ति का प्रयोग करने हुए इस संविधान के किसी उपसद का संविधान, संविधान अथवा निरसन के रूप में संगोपन, या अनुच्छेद में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी।

(२) इस संविधान के संशोधन का भूतपान उम प्रयोजन के लिए संशोधन ससद के किसी सदन में पुरस्थापित करके ही किया जा सकेगा तथा जो प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य-समस्या के बहुमत में तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आठिगई में अपूर्ण बहुमत में वह विधेयक पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के मंत्र राखा जायगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और जो मंत्र विधेयक के निरघना के अनुसार संशोधित हो जायगा

परंतु यदि ऐसा कोई संगोपन—

(क) अनुच्छेद ५४, अनुच्छेद ५५, अनुच्छेद ७०, अनुच्छेद १६२, या अनुच्छेद २४१ में, अथवा

(ख) भाग ५ के अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ४, या भाग ११ के अध्याय १ में, अथवा

(ग) ससद अनुसूची की सूचिया में से किसी में, अथवा

(घ) ससद में राज्या के प्रतिनिधित्व में, अथवा

(ङ) इस अनुच्छेद के उपसद में,

कोई संविधान करना चाहता है तो ऐसे उपसद करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए उपस्थित किया जान के पश्चात् उक्त संशोधन के लिए राज्या में स वम से वम आये राज्या के विधानमंडल का उस प्रयोजन के लिए उन विधानमंडल में पारित करना होगा अतः समय भी अपेक्षित होगा।

(३) अनुच्छेद १३ की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किया गया किसी संशोधन को लागू न होगी।

सबसे पहले हाशिये पर दी गयी टिप्पणी के संशोधन की गेट मंत्रा सफल हुई है क्योंकि पहले की टिप्पणी सिर्फ "संविधान के संशोधन का विधान प्रक्रिया" की और भोलकनाथ मुखर्जी ने इसी को आधार बना कर यह प्रमाणित किया कि इसमें सिर्फ प्रक्रिया बतायी गयी है उसकी शक्ति नहीं दी गयी है।

दूसरे, अनुच्छेद ३६८ में एक नया खण्ड जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद १३ (१) के मातहत संविधान में किये गये किसी संशोधन का अनुच्छेद १३

लागू न होना स्थापित किया गया। यह भी गालतनाथ मुखदम के केन्द्रीय तक को बाटने के लिए किया गया जिसमें कहा गया था कि संविधान में कोई संशोधन भी अनुच्छेद १३ के अन्तर्गत एक कानून है और इसलिए, उसका मूल अधिकारों के अनुरूप होना पड़ेगा।

२५वें संशोधन के प्रथम भाग का सारान्तर्गत था “प्रतिफल” शब्द की जगह “राशि” शब्द का रखा जाना। इस प्रकार नया अनुच्छेद ३१ (२), संशोधन के बाद, इस तरह हुआ गया

कोई सम्पत्ति सावजनिक प्रयोजन के लिए ही और केवल एसी विधि के प्राधिकार से अनिवार्य अर्जित या अधिग्रहीत की जायगी जो सम्पत्ति के अजन या अधिग्रहण का, ऐसी राशि के बदले जो उस विधि द्वारा नियत की जाय या जो ऐसे सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाय और एसी रीति से दी जाय जो उस विधि में विनिर्दिष्ट हो, उपबंध करनी है, और ऐसी किसी विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि इस प्रकार नियत या अवधारित राशि पर्याप्त नहीं है अथवा ऐसी पूरी राशि या उसका कोई भाग नकद न दिया जा कर अन्यथा दिया जाना है

परंतु अनुच्छेद ३१ के खंड (१) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा-संस्था की सम्पत्ति के अनिवार्य अजन के लिए उपबंध करने से संबंधित विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सम्पत्ति के अजन के लिए ऐसी विधि के अधीन जो राशि नियत या अवधारित की जाय वह ऐसी हो जो उस खंड के अन्तर्गत प्रत्याभूत अधिकार को निर्विधित या निराकृत न करे।

उद्देश्य स्पष्ट था प्रथमतः उच्चतम न्यायालय ने ‘प्रतिफल’ शब्द का राज्य द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली सम्पत्ति के बाजारी मूल्य के अर्थ में जिस तरह व्याख्यायित किया था, उससे बचना, और दूसरे अंश की जान वाली ‘राशि’ (संगोहित अनुच्छेद में मूल महत्व का शब्द) के परिमाण का फसला पूरी तरह राज्य पर छोड़ना और उसको न्यायिक पुनरीक्षण के दायरे में कर देना।

अनुच्छेद ३१ में एक नया अनुच्छेद था, जो इस प्रकार है

अनुच्छेद १३ में किसी बात के होते हुए भी कोई विधि, जो अनुच्छेद ३६ के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित तत्वों को सुनिश्चित करने के

लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर तूय न समझी जायगी कि वह अनुच्छेद १४ अनुच्छेद १६ या अनुच्छेद ३१ द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है अथवा उसे छीनती या घून करती है, और जिस विधि में यह घोषणा हो कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, उस पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती

परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनायी जाय वहां इस अनुच्छेद के उपरान्त उसे तब तक लागू न होंगे जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित किया जाने के पश्चात्, उसकी अनुमति न मिल गयी हो।

[काले जशरा में दिय गये अंश को घमाधिराज केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य की १९७२ की प्रादेश-माचिका (रिट पीटिशन) न १३५ में न्यायालय ने बहुमत में अवैध घोषित कर दिया था (२४४ १९७३)]

इस अनुच्छेद के अन्तर्गत हमारे संविधान के इतिहास में पहली बार एक निदेशक सिद्धांत का मूल अधिकारों से ऊपर रखा गया।

अनुच्छेद ३६ (ख) और (ग) इस प्रकार हैं

राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

- (ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बड़ा हो कि जिस से सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो,
- (ग) जायिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धन और उत्पादन साधना का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केंद्रण न हो,"

ये दो अनुच्छेद सरकार को भारतीय समाज के समाजवादी रूपान्तरण की दिशा में आगे बढ़ाने का निर्देश देते हैं। नये अनुच्छेद ३१ (ग) को जारी कर संसद ने यथायत्न यह स्पष्ट घोषित कर दिया कि व्यक्तियों के अधिकारों (जो तत्काल मूल अधिकार हैं) को अनुच्छेद ३६ (ख) और (ग) के अन्तर्गत संविधान के इस निदेश के कार्यान्वयन के रास्ते में खड़ा नहीं होने दिया जायगा।

संविधान में ये दो संशोधन (२४वें और २५वें) गत वर्ष (१९७२) के अंतिम भाग में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए पेश हुए। और ६६ काय दिवसा तक सुनवाई के बाद, जो न्यायालय के इतिहास में सबसे लंबी

अवधि है, २४ अप्रैल १९७३ को, यानी मुख्य 'यायाधिपति सीकरी के पद मुक्त होने से ठीक दो दिन पहले, निणय सुनाय गये ।'

ये निणय जो कुन मिला कर ग्यारह थे, एक बार फिर मिश्रित किम्म के निकले—स्पष्टता और मनिभ्रम के मिश्रण ।

एक ओर छै 'यायाधीश ने, 'यायाधीश राय के नेतृत्व मे (वह उस समय 'यायाधीश थे), स्पष्टन व्यवस्था दी है

(१) मोनबनाय मुक्कमे म गलत फैसला दिया गया था और वह र किया जाता है ।

(२) सविधान म सशोधन करन के विषय मे ससद की शक्ति की कोई सीमा नही है, और चूकि अनुच्छेद ३६८ म बताया गयी प्रशिया का मन्नी से पालन किया गया है इसलिए २४वें और २५वें सशोधन पूणतया बध हैं ।

(३) अनुच्छेद ३१ ग म 'यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त करन की जो व्यवस्था की गयी है, जिसके जरिय ससद ने इस बात के कि किसी विधायक विशेष मे अनुच्छेद (ख) और (ग) को प्रभावी बनाया गया है या नही, 'यायिक पुनरीक्षण पर जो पाबंदी लगायी है वह भी बंध है ।

किंतु जहा तक अय फैसला का सम्बन्ध है, उनमे कोई सुसगतता या स्पष्टता अथवा कोई समान सूत्र पाना कठिन है । निश्चय ही उनमे से चार यायाधीश पहले छै 'यायाधीशो से इस मत पर सहमत थे कि गोलकनाथ मुक्कमे मे फैसला गलत दिया गया था, मगर साता 'यायाधीश यह मत प्रकट करते प्रतीत हाते है कि अनुच्छेद ३६८ मे सशोधन की शक्ति, जिस तरह वह २४वें सशोधन से सन्नाहित किया गया है, इतनी विस्तृत नही कि वह अपनी सीमा म ऐमे सशोधनो को ग्रहण कर सके जिनस सविधान का बुनियादी ढांचा और सरचना निराहत" (रद्द) हो जाय । मगर इस समान तक के बावजूत, इन पांच अलग अलग फैसलो को पढने से यह पता नही चलता कि निश्चित रूप स कौन सा बुनियादी ढांचा और सरचना है जो इन 'यायाधीशो की राय म ससद की सशोधन शक्ति से ऊपर और बाहर है तथा कौन से ऐस अनुच्छेद हैं जिनम सशोधन नही किया जा सकता ।

निश्चय ही, उनमे स 'यायाधीश खना स्पष्ट कहते हैं कि मूल अधिकार और सम्पत्ति अधिकार सविधान के 'बुनियादी ढांचे और सरचना का अग नही हैं । और अगर 'यायाधीश राय के नेतृत्व वाले छै 'यायाधीशो के दृष्टिकोण

के साथ उनका दृष्टिकोण जोड़ दिया जाय, ता मविधान के भाग ३ में सगो धन के विषय में ससद का अधिकार स्पष्टतः भाय होता है और गोलकनाथ मुकदमा दफन हो जाता है।

मगर न्यायाधीश हगडे और मुख्यों फरमाते हैं कि मूल अधिकार "सगोधिनी" किये जा सकते हैं, 'रद्द' नहीं किये जा सकते, हालांकि उनके लम्बे फैसले में यह पता चलना कठिन है कि "सशोधन" और "रद्द" के बीच क्या रेखा खींची जाय।

सशोधन के इस प्रश्न पर इन दो न्यायाधीशों का सार निम्नलिखित है

हमें विश्वास हा गया है कि ससद को सविधान के बुनियादी तत्व या मूल पहलुओं को, जैसे भारत की प्रभुसत्ता, हमारी राज्य व्यवस्था का जन साक्षिक चरित्र, दण की एवता, सविधान के अंतर्गत व्यक्ति के लिए आरक्षित की गयी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सारभूत पहलू रद्द करने या उनका सारस्त्व छीनने का कोई अधिकार नहीं है। न ही ससद को एक लोक-न्यायाधीशों के राज्य तथा 'यावपरक' समाज का निर्माण करने सम्बन्धी निदेश को रद्द करने का अधिकार है।

इसलिए जा बात स्पष्ट नहीं है उसको और अधिक अस्पष्ट बनाने के लिए निम्नान 'यायाधीशों' न आग जोड़ा

य सीमाएँ केवल उदाहरणात्मक हैं, सर्वांगपूर्ण नहीं,

इस प्रकार न्यायाधीशों लोग किसी भी समय अपनी मर्जी के अनुसार ऐसी बातें जोड़ सकते हैं जिनको व सविधान के मूल तत्वों का अंग महसूस करें।

और तब किन 'यायाधीशों' ने निष्कर्ष निकाला

मगर, इन सीमाओं के बावजूद, इस पर सदेह नहीं किया जा सकता कि सशोधन अधिकार एक व्यापक अधिकार है और वह सविधान के प्रत्येक अनुच्छेद तथा प्रत्येक भाग पर लागू होता है। (जोर मेरा)।

मेरा ख्याल है कि यह बात 'यावपूर्वक' बही जा सकती है कि 'यायाधीशों' हगडे और मुख्यों द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से स्थिति उससे भी अधिक गिराव गयी जितनी कि गोलकनाथ मुकदमे के फैसले के कानून बन जाने के समय थी। गोलकनाथ फैसले में उच्चतम 'यायालय' ने कम से कम यह मत तो

प्रकट किया था कि मूल अधिकारों का छोड़ कर गोप प्रत्येक अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है—यह स्थिति सुनिश्चित थी और इसी का सुधारन के लिए २४वां संशोधन पारित किया गया था ।

मगर अब एक नयी अवधारणा आ गयी—मूल तत्वा या बुनियादी पहलुओं की अवधारणा, जिसमें मूल अधिकार शामिल प्रतीत होते हैं और साथ ही उसमें हर अर्थ वात भी शामिल हो सकती है जिसके विषय में 'यायाधीन' महसूस करें कि उसको शामिल किया जाना चाहिए । और ये मूल तत्व भी संशोधन किए जा सकते हैं बशर्ते कि उन्हें 'रद्द' न किया जाय या उनका "सारतत्व" न 'छीना जाय ।'

'यायाधीन' शैलत और ग्रावर ने भी कोई भिन्न दृष्टिकोण नहीं अपनाया । उन्होंने ऐसी वाता की सूची शुरू की जिनको वे "संवैधानिक ढांचे के मूल तत्व" कहते हैं और चेतावनी दी कि "इह सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ।' और फिर उन्होंने निम्नलिखित सूची दी

- (१) संविधान की सर्वोच्चता ।
- (२) सरकार का जनतान्त्रिक और संसदीय स्वरूप तथा देश की प्रभुसत्ता ।
- (३) संविधान का धर्मनिरपेक्ष और सघीय चरित्र ।
- (४) विधानमंडल कायपालिका और 'यायपालिका' के अधिकारों का सीमांकन ।
- (५) भाग ३ में दिये गये मूल अधिकारों और विभिन्न स्वतन्त्रताओं द्वारा आरक्षित व्यक्ति का सम्मान तथा भाग ४ में सम्मिलित कल्याणकारी राज्य के निमाण का निदेश ।
- (६) राष्ट्र की एकता और अखंडता ।

यहां भी हम एक अस्पष्ट स्थिति में छोड़ दिया गया है जो 'यायाधीन' की इस चेतावनी से कि ये छे सूत्र उदाहरणात्मक मात्र हैं सर्वांगपूर्ण नहीं और अधिक अस्पष्ट हो गयी है ।

और फिर 'यायाधीन' हेण्डे और मुखर्जी की ही तरह 'यायाधीन' का अंतिम उपहार यह है कि अनुच्छेद ३६८ के अधिकार इतने काफी विस्तृत हैं कि संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद के संशोधन की इजाजत मिलती है जब तक कि उसके मूल तत्व रद्द नहीं किये जाय या उनकी अस्मिता नहीं छीनी जाना —इसका अर्थ जा भी हो ।

मुख्य 'यायाधिपति' सीकरी भी ऐसा मूल ढाँचा जा सशोधन के अधिकार से बाहर है, निम्नलिखित बातों से निमित्त बनाने हैं

- (१) सविधान की सर्वोच्चता ।
- (२) सरकार का जनतांत्रिक और संसदीय स्वरूप ।
- (३) सविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र ।
- (४) विधानमंडल, कायपालिका और 'यायपालिका' के अधिकारों का पृथक्करण ।
- (५) सविधान का सघीय चरित्र ।

'यायाधीश' जगन्नाथ रेड्डी इस बात को जोर भी सामान्य शब्दों में पेश करते हैं । उनकी स्थापना निम्नलिखित है

अनुच्छेद ३६८ के अंतर्गत संशोधन के अधिकार काफी विस्तृत हैं, किन्तु इतने काफी विस्तृत नहीं कि ये इस तरह पूर्णतया रद्द कर दें या रद्द करने के बराबर हो जायें या इस तरह सारतत्त्व छीन लें या नष्ट कर दें कि उन मूल अधिकारों में से किसी को या सविधान के बुनियादी ढाँचे के सारभूत तत्त्वों को और उसकी पहचान को नष्ट कर दें ।

और फिर थोड़ा ढाँडस बचाने के लिए 'यायाधीश' महोदय ने जाड़ा

इन सीमाओं के भीतर समस्त प्रत्येक अनुच्छेद को संशोधित कर सकती है ।

स्पष्ट ही इन छह 'यायाधीशों' की घोषणाओं में से ऐसा कोई मुनिदिशित या स्पष्ट और बोधगम्य नियम प्राप्त करना असम्भव है जिसमें यह समझन का विद्वत्सनीय आधार प्राप्त हो जाय कि संशोधन का अधिकार ठीक ठीक कितना व्यापक है उसकी सीमा कहाँ तक फैलती है और क्या हम उस सीमा को पार करते तथा वज्रित क्षेत्र में प्रवेग करने माने जायेंगे, यानी कि किस मूल में यह माना जायगा कि सविधान का मूल ढाँचा रद्द किया जा रहा है या उसका सारतत्त्व छीना जा रहा है ।

इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि इन छह 'यायाधीशों' का दृष्टिकोण 'यायालय' का प्रधान दृष्टिकोण बन जाना तो सविधान में संशोधन सम्बन्धी संसद के अधिकार-क्षेत्र के मामले में पूर्ण अनिश्चितता फैल जानी और यह अनिश्चितता उससे भी अधिक ऊँची थोपी गयी होती जो मोरारजी देसाई के दावों के दाद पदा हुई थी ।

स्पष्ट है कि अगर अंतिम छे 'यायाधीश' का दृष्टिकोण 'यायालय' का प्रधान दृष्टिकोण बन जाता तो कानून की स्थिति के विषय में अनिश्चितता न सिर्फ जारी रहनी, बल्कि और अधिक बढ़ जाती ।

इसलिए जहाँ तक 'यायालय' के भविष्य का प्रश्न है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था । हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था के स्थायित्व और प्रगति के लिए कानून की स्थिति के विषय में स्थिरता और निश्चितता एक जीवन्त प्राथमिक शक्ति है । और इस तरह की निश्चितता एक ऐसी 'यायपालिका' से ही सम्भव है जो अपने फैसलों के विषय में सुस्पष्ट होती है, यथासम्भव कम से कम बात अस्पष्ट और अनिश्चित छोड़ती है और अपनी बुनियादी स्थितियों का समय समय पर बदलती नहीं और उनमें भिन्नता पैदा नहीं करती ।

हाल के मामले में उच्चतम 'यायालय' के फैसले से अब स्पष्ट है कि गोलकनाथ मुकदमे का फैसला गलत था, स्पष्टतया गलत था । उस मामले में जो तरह 'यायाधीश' फैसला करने बैठे थे, उनमें से दस न यह मत व्यक्त किया था, यानी वह लगभग सबसम्मति मत था । लेकिन उस मामले में सविधान की व्याख्या में जो अनिश्चितता पैदा हुई उसके कारण देश को भारी क्षति पहुँची । और निश्चय ही अब जब कि 'यायालय' ने उस फैसले से अपने को अलग कर लिया है, उसका मुख्य दायित्व और कर्तव्य यह होना चाहिए कि दृष्टिकोण सम्बन्धी उस स्थिरता को वह पुनः प्रतिष्ठित करे, जो उस विनाशक फैसले से पहले अस्तित्व में थी ।

०

४. जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में न्यायाधीशों का सचयन

ऐसे व्यक्तियों को चुनने में जो न्यायालय में नियुक्ति के लिए उपयुक्त और योग्य हों, राज्य के व्यापक मामला पर और आज भारत में हमें जिन निष्पकारी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन पर उनके दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना भी महत्वपूर्ण है। अगर न्यायाधीश को इस निगाह से देखा जाता है कि वह तब के शुद्ध प्रकाश से निर्देशित होता है, उसका अपना कोई दृष्टिकोण नहीं होता—विशेषकर आर्थिक नीति के मामलों में—तो यह जीवन की वास्तविकताओं की अपेक्षा करना होगा।

पचास वर्ष से अधिक समय पहले एक महान अमरीकी न्यायाधीश बेंजामिन कार्डोजो ने लिखा था

हम सब में एक प्रवृत्ति धारा होती है, उसे आप दर्शन कहें या न कहें, या विचारों और क्रियाकलापों का एक समर्थन और दिशा प्रदान करती है। न्यायाधीश भी अन्य प्राणियों की भाँति उस धारा से बच नहीं सकते। सारी जिंदगी ऐसी शक्तियाँ उनके साथ खींच-तान करती रहती हैं जिन्हें वे पहचानते नहीं और जिनको वे नाम नहीं दे सकते—जैसे, विरासत में

मिनी मनोवृत्तियाँ, परम्परागत विश्वास, अजिन आम्ब्याए, और इन सब का परिणाम होता है जीवन सम्बन्धी एक दृष्टि, सामाजिक आवश्यकताओं की एक अवधारणा, एक भावना जिसे जेम्स के शब्दों में "ब्रह्माण्ड का सर्वांग चल प्रयाग और दवाव" कहते हैं जो, उस समय जब कि तब सुचारु रूप में सन्तुलित किये जाते हैं, यह निर्धारित करता है कि चयन क्या होगा।^१

इसलिए "यायालय में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के "दशन," 'जीवन सम्बन्धी दृष्टि' और "सामाजिक आवश्यकताओं की अवधारणा" की परीक्षा करना महत्वपूर्ण है। नियुक्ति के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के दशन की अवहेलना या उपेक्षा करना मूल्यता से अधिक चोख होगी, क्योंकि अंतिम विश्लेषण में जब "तब सुचारु रूप से सन्तुलित किये जाते हैं" तो यह 'यायाधीश' का दशन ही होता है जो यह निर्धारित करता है कि उसका "चयन क्या होगा।"

हमें अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। 'यायाधीश' के भी अपने विचार होते हैं—राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर। और जब वे उच्चतम 'यायालय' के सदस्य बन जाते हैं तब वे उच्चतम सामाजिक महत्त्व के मुख्य मुद्दों पर फैसले देते हैं जिनमें उनके राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक विचार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किये बिना नहीं रहते।

उच्चतम 'यायालय' के मुख्य 'यायाधिपति पद' शक्ति शास्त्री न जब निम्न लिखित बात कही थी तब इसी बिंदु पर बल दिया था

यह अपरिहार्य है कि फैसले में भाग लेने वाले 'यायाधीश'ों के सामाजिक दशन और मूल्य सम्बन्धी मानदण्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें।

इस मामले का राष्ट्रपति थ्योडोर रूजवेल्ट ने ८ दिसम्बर १९०८ का अमेरिका की संसद के नाम भेजे अपने संदेश में जिस प्रकार रखा, उसमें बेहतर या स्पष्टतावादी तरीके से शायद अब किसी ने नहीं रखा।

१ "दि नेयर ऑफ दि जुडीशियल प्रोसेस" (आर्थिक प्रक्रिया की प्रकृति), स्पोर्ट्स-वार्शियनमाला पृष्ठ १२ यह 'वार्शियनमाला' बेंजामिन एन कार्डोत्तो ने जो बाद में अमेरिका के उच्चतम 'यायालय' के महक्कती (प्रेसिडेंट) 'यायाधीश' पद पर रहे (१९३२-१९४८), १९२० में येल विश्वविद्यालय में दी थी और उसमें आर्थिक मरितीय की कार्य प्रकृति पर क्लेमिन्टी योगदान माना जाता है अपेक्षाकृत लम्बा उद्धरण परिशिष्ट १ में दिया गया है।

हमारे देश में मुख्य बानून निर्माता सापेक्ष "यायाधीन" हो सकते हैं और अक्सर होते हैं क्योंकि सत्ता का अन्तिम पद उही का है। हर बार जब ये अनुपपन्न, सम्पत्ति, निहित अधिकार, बानून की रीति प्रक्रिया और स्वतन्त्रता की व्याख्या करते हैं तब वे आवश्यक रूप से सामाजिक दान की एक व्यवस्था को बानून के अंगों के रूप में रीति बनाते हैं, और बूनि ऐसी व्याख्या मूलभूत होती है, व समस्त बानून निर्माण प्रक्रिया को सिद्धा देते हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रदान पर "यायालय" के फैसले उनके आर्थिक और सामाजिक दान पर निर्भर करते हैं, और बीसवीं सदी में अपनी जनता की "रातिपूर्ण प्रदान" के लिए हम सर्वोपरि आभागी हूँ उन "यायाधीन" के जो बीसवीं सदी के आर्थिक और सामाजिक दान के समर्थक हैं, उस दान के नहीं जो काफी ज़रूरत पुराना पद चुना है और जो स्वयं आर्थिक परिस्थितियों की उपज का।

इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि "यायालय" में निर्धारित नियुक्त किया जाना चाहिए और निर्धारित इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि उग्रा प्रधान किस बनाना चाहिए, य सभी बातें समत ह। किसी भी देश के इतिहास के हर चरण में जब कभी उच्चतम "यायिक" पद पर नियुक्ति के प्रदान पर विचार किया गया, नियुक्ति अधिकारी सदा उन वस्तुओं का जो देश के सामने उपस्थित होते हैं, उस दिशा का जिसमें दान बढ़ना चाहता है और "वक्त के तवाजे" का ध्यान रखता है। बिनापकर, किसी भी एंग्लो-मेक्सन देश में उच्च "यायिक" पदा पर नियुक्तिया पदोन्नति या वरिष्ठता के आधार पर नहीं की गयी। धार्मिक में, इस प्रदान पर राष्ट्रमण्डल के विभिन्न देशों और अमरीका की स्थिति का अध्ययन मानविक और लाभप्रद है।

हमारे "यायालय" में दुनिया के जिन मुख्य दानों के फैसला और हज़ारों की अक्सर बर्बा की जाती है, वे हैं अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा और आस्ट्रेलिया। और, इन चारों दानों में ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि जिससे अनुसार "यायाधीन" का "यायिक" व्यवस्था के उच्चतम पद पर श्रद्धा बन्दम पदोन्नत करते हुए नियुक्त किया जाता हो।

संयुक्त राज्य अमरीका

अमरीका में "यायिक" नियुक्तियों का पार्टी की विचारधारा के आधार पर किया जाना स्वीकृत है। १९३३ में १९७१ की अवधि में उच्चतम "यायालय" में २६ "यायाधीन" नियुक्त किये गये। इनमें से २२ सत्ताधारी राष्ट्रपति की पार्टी के थे, चाहे यह पार्टी रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट। राष्ट्रपति फ्रेडरिक्स

रजिस्ट्रार ने, जो बारह वष तक राष्ट्रपति रहे, नौ न्यायाधीश नियुक्त किए थे जिनमें से आठ उनकी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, के थे।

एक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है

राष्ट्रपतियों ने उच्चतम न्यायालय के लिए विशेष व्यक्तियों को क्यों चुना, इसके कारण भिन्न भिन्न हैं। नियुक्ति निर्धारित करने में अवसर विचारधारा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, किंतु प्रायः कुछ अन्य तत्व भी उतने ही निर्णायक प्रतीत होते हैं। राजनीतिक पारितोषिक, व्यक्तिगत मंत्री पार्टी की सेवा और यहां तक कि पहले का न्यायिक अनुभव उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियों को सही ठहराने के लिए बड़े कारण रहे हैं। सभी राष्ट्रपतियों ने उच्चतम न्यायालय के अधिकांश सचयन स्वयं अपनी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों में से किए हैं। किंतु यह भी रिवाज रहा है कि प्रत्येक प्रमुख राजनीतिक पार्टी का कम से कम एक सदस्य उच्च पद पर रखा जाय और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रपतियों ने समय समय पर 'पार्टी से बाहर' के न्यायाधीश चुने।

(जोयल बी. ब्रासमैन, 'पॉलिटिक्स आफ जूडिशियल सेलेक्शन')

इसलिए स्थिति स्पष्ट है। न्यायाधीश जितना अपन न्यायिक ज्ञान और कौशल के कारण चुने जाते हैं उतना ही अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण भी।

अमरीकी पाण्डित्य की सर्वांग सम्पन्नता की विधिष्ठता के साथ स्टुअर्ट नागेल ने "राजनीतिक पार्टी से सम्बंध और न्यायाधीशों के फैसले" का विश्लेषण किया है। विस्तृत विचार के बाद नागेल ने देखा कि "१५ तरह के मुकदमों में (लिखत में तमाम तरह के मुकदमों को इन १५ श्रेणियों में बाटा है) रिपब्लिकन न्यायाधीशों की तुलना में वही अधिक हृदय तक डेमोक्रेटिक न्यायाधीशों ने अपने-अपने न्यायालयों में जीसत में ऊपर ऐसे फैसले किये जिनको एक उदार पक्षी दिशा में माना जा सकता है।"

इसलिए उनका निष्कर्ष है कि रिपब्लिकन न्यायाधीशों की तुलना में डेमोक्रेटिक न्यायाधीशों से अधिक आशा की जा सकती है कि वे प्रस्तावित उदार पक्षी दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे और इसलिए स्पष्टतः एक डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति एक डेमोक्रेटिक न्यायाधीश नियुक्त करना पसंद करेगा, और यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि उदारता रुझान होने की यह सम्भावना दृष्टिकोण में स्वतंत्रता और न्यायिक ईमानदारी के अभाव से नहीं पैदा होती बल्कि इसके विपरीत सम्बंधित न्यायाधीश के मूलभूत दशन और दृष्टिकोण से पैदा होती है। उच्च

राजनीतिक नियुक्तियां तथा 'यायाधीशमण्डल (बेंच) के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध हाल के दो उदाहरणों से सिद्ध होना है।

हाल में अवकाश प्राप्त मुख्य 'यायाधिपति वारेन १९५३ में इस 'यायिक पद को ग्रहण करने से ठीक पहले कैलिफोर्निया के रिपब्लिकन राज्यपाल थे। १९४८ में वह जान डेवी के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार थे और १९५२ के रिपब्लिकन सम्मेलन में जनरल ड्वाइट आइज़नहावर के जवदस्त समर्थक थे।

उसी 'यायालय के 'यायाधीश विनियम ओ डगलस फ्रैंक्लिन हज्वेल्ट के 'यू डील' काल में वाशिंगटन में सरकारी 'मृग तथा मुद्रा विनियम आयोग के अध्यक्ष रहे थे और अपनी नियुक्ति से ठीक पहले तब 'डेमोक्रेटिक पार्टी' में सशक्त राजनीतिक शक्ति थे। इसी प्रकार अमरीका के उच्चतम 'यायालय तथा अन्य संघीय न्यायालया, दोनों के ही अनेक अन्य 'यायाधीश किसी न किसी समय अपनी नियुक्ति के समय तब मन्त्रिपरिषद् से घनिष्ठत सम्बन्धित थे और राज्य स्तर पर नियुक्त किए गये 'यायाधीशों के मामले में यह सम्बन्ध अक्सर और अधिक घनिष्ठ रहा है।

इसलिए इन नियुक्तियों का निष्कर्ष से परीक्षण करने वाले एक विद्वान ने टिप्पणी की है

निश्चय ही, अमरीकी उच्चतम 'यायालय के सामने जो 'सावजनिक प्रश्न आते हैं, उनकी प्रकृति और 'नियंत्रण तथा सन्तुलन' की अमरीकी व्यवस्था में सरकार की तीसरी शाखा के रूप में उसकी संवैधानिक भूमिका से आम तौर पर यह निदिशित होता है कि उसके पदाधिकारी 'सावजनिक जीवन से, विशेषकर उस 'यायालय के नीति सम्कार के प्रकाश में, भरती किये जायें।

(“कनैडियन कांस्टीट्यूशनल ला इन ए माइन पर्सपेक्टिव”, यूनिवर्सिटी आफ टोरंटो प्रेस, १९७०, पृ. ३४६)

राजनीतिक विचारधारा और दृष्टिकोण के आधार पर 'यायिक नियुक्तियां करने की यह प्रवृत्ति जनतांत्रिक व्यवस्था में कैसे उचित ठहरायी जा सकती है ? प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपना युग का राजनीतिक दशन और अपनी विचारधारा होती है तथा इसी तरह प्रत्येक 'यायाधीश के, अपने ही तरीके से, अपने पूर्वग्रह और पूर्वधारणाएँ, अपना दशन और जीवन दृष्टिकोण, होता है। अपने सदन में राष्ट्रपति हज्वेल्ट ने जिस चीज पर बल दिया (जिसका उदाहरण पृष्ठ २७ पर दिया जा चुका है) था, यह था कि 'यायाधीश समेत हर व्यक्ति

का अपना दशन होता है और वह दशन महत्वपूर्ण है, परीक्षा यह करनी होती है कि रुजवेट के शब्दों में, वह 'वाफी अरमे पहले पुराना पड चुमा दशन' है जा पीछे की ओर देखता है या एक आधुनिक दशन है जो आग की ओर देखता है।

एक बार फिर यायावीश वजामिन एन बाडोजो की क्लासिकी कृति 'दि नेचर आफ दि जुडीशल प्रासस' ('यायिक प्रक्रिया की प्रकृति', जो बहुत पहले, १९२१ में, प्रकाशित हुई थी) से वे शब्द उद्धृत करें जिनका भाषा के सौदय और विचारा की परिगुद्धि, दोनों के मामले में, गायद ही कोई मान दे सका है। उन्होंने लिखा है

चेतना की गहराई में नीचे अय शक्तिया है रचिया और अरचिया
 पूववृत्तिया और पूवग्रह, मूल प्रवृत्तियो और भावावेगा तथा आदना और
 विश्वासो की गुत्थिया, जो मनुष्य का निर्माण करती है वह चाह 'यामा
 धोश हो या वादी प्रतिवादी। तदी कामना थी कि इस विषय का और
 अधिक अनुशीलन करना क लिए मेरे पास समय और अवसर होता। जैसा
 भी हो, मैं यहा उसके अस्तित्व के विषय में स्मरण कराने से अधिक
 कुछ नहीं कर सकता। इस विषय के विचार विनिमय में या शायद उस
 पर विचार करने से इनकार करने में, स्पष्टवादिता की कुछ ऐसी कमी
 है मानो इस बात की याद दिलाये जान से कि 'यायाधीन भी मानवीय
 सीमाओं के अधीन है उनके प्रति सम्मान और विश्वास समाप्त हो
 जायगा।' मुझे गौरव की अवधारणा में सन्देह नहीं है जो उन्हें परेशान
 और दिशा भ्रमित करने वाली शक्तियों के बहाव से अलग और बाहर
 विशुद्ध तकवुद्धि के ससार में पहुंचा देती है। तब भी अगर 'यायिक
 प्रक्रिया के मेरे विश्लेषण में यथाथ का लेगमात्र अंग भी है तो वे उन
 हिमानी और सुंदर शिखरा पर अकेले खड़े नहीं पाये जा सकते, और अगर
 हम यह कह कि वे पाये जाते हैं तो इस बात से हम सत्य के लभ्य की
 सहायता नहीं कर सकते। जो भारी ज्वार भाटे और धाराएं सप मनुष्या
 की सराबोर किय रहती हैं वे अपने रास्ते से हट कर 'यायाधीशों को
 प्रशंसा कर नहीं निकल जाती। (पृष्ठ १६७-६८)।

जिस वस्तुपरकता और ईमानदारी से अमरीका के महाननम यायिक

१. मैं समझता हूँ कि यह तीसरी मगर विनम्र टीका आन भारन में चल रहे बाद विवाद पर भी मनी भाति लागू हो सकती है

मस्तिष्क में से एक सवमाय विद्वान ने इन विचित नाजुक समस्याओं का सामना किया और उनकी परीक्षा की, उससे शायद भारत में हम लोग भी सीख सकते हैं ।

ग्रेट ब्रिटेन

ब्रिटेन में 'यायाधीश' को पदोन्नति देने की कोई स्वीकृत पद्धति नहीं है । आम तौर पर अगर एक व्यक्ति काउटी (मजल) 'यायालय' का 'यायाधीश' नियुक्त हो जाता है तो वह काउटी 'यायालय' का 'यायाधीश' बना रहता है और उसी पद से अवकाश ग्रहण करता है । ऐसा लगता है कि सिर्फ एक बार एक ऐसे 'यायाधीश' को उच्च 'यायालय' में नियुक्त किया गया था ।

किंतु बरिष्ठ 'यायाधीश' में से उच्च 'यायालय' से अपील 'यायालय' के लिए, अथवा उच्च 'यायालय' या अपील 'यायालय' से राज सभा (हाउस आफ लॉर्ड्स) के लिए पदानति की जाती है । इन तीनों ही 'यायालयों' में स प्रत्येक में सीधी नियुक्ति की गयी है और अपील 'यायालय' या राज सभा के रिक्त स्थान की भी पूर्ति जवसर उच्च 'यायालय' के बजाय वकीलों में से की जाती है । तक यह है कि उच्च 'यायालय' का एक अच्छा 'यायाधीश' मुख्यतः विचारण (ट्रायल) 'यायाधीश' होता है और यह आवश्यक नहीं कि विचारण 'यायाधीश' अपीलेट के काम में भी अच्छा 'यायाधीश' मिष्ट हो और विपरीतत भी यही बात है ।

लेकिन यह नहीं है कि इंग्लंड में 'राजनीतिक दावा' की उपेक्षा की जाती है । जार एम जैक्सन ने अपनी पुस्तक 'दि मशीनरी आफ जस्टिस इन इंगलंड' ('इंगलैंड में 'यायतंत्र') पृ २०६-२१० पर लिखा है

श्रेष्ठतम पद, लाड चीफ जस्टिस का पद, राजनीतिक सेवाओं के लिए लग भग एक पारितोषिक होता है ।

और जैक्सन ने आगे शीका की है

इसलिए राजनीति न केवल 'यायिक' पद में वृहत्तर परिवर्तन ला सकती है बल्कि और अधिक वाछनीय पदों तक भी प्रत्यक्षत पहुँचा सकती है । पदोन्नति की व्यवस्था से शायद और भी अधिक बुरे परिणाम होंगे । एक बार व्यक्ति 'यायाधीश' बन जाय तो उसे यथासम्भव स्वतंत्र बनना चाहिए, अगर अपने 'यायिक' जाचार से सरकार को प्रसन्न कर वह पदोन्नति प्राप्त करता है तो यह हमेशा सम्भव है कि वह सदा अपनी भावी

उनति की ही बात सोचता रहेगा। पदोन्नति की आकांक्षा शायद फ्रांसीसी 'यायापालिका' का सबसे अधिक निबल अंग है, एक छोटा 'यायाधीन' यह महसूस कर सकता है कि अगर वह अपने सेवा विभाग के प्रधान का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा तो उसको नज़र दाज किया जा सकता है और वह अपने मौजूदा ग्रेड में ही रह जायगा। इंग्लैण्ड में नियुक्ति के राजनीतिक दावों के दबाव कम से कम उस समय समाप्त हो जाते हैं जब नियुक्ति कर दी जाती है। ऋण अदा हो जाता है और राजनीतिक हिंसा ब्रिक्ताय बंद कर दिया जाता है।

इंग्लैण्ड में उच्चतम 'यायिक' पद के सचयन को राजनीति किस हद तक निर्धारित करती है इसको जिस तरीके से १९२० में लायड ज्याज की सरकार के एटर्नी जनरल सर गौडन हेवट मुख्य 'यायाधिपति' बने, उससे देखा जा सकता है। उस समय जब लाड रीडिंग मुख्य 'यायाधिपति' थे, सर गौडन हेवट ससद में लायड ज्याज के दाहिने हाथ थे। लाड रीडिंग, जिन्होंने १९१३ में मुख्य 'यायाधिपति' के पद की पूर्ति की थी, किसी राजनयिक पद या अन्य उच्च राजनीतिक उत्तरदायित्व के आकांक्षी थे और उनके उत्तराधिकारी का प्रश्न विचाराधीन था।

उस समय लायड ज्याज ने हेवट से पूछा कि क्या उन्हें 'यायिक' या कानूनी पद में कोई दिलचस्पी है और उन्हें स्पष्ट उत्तर मिला "मेरा उत्तर बहिर्बन्ध रूप से, 'यायिक' पद के पक्ष में है।"

लायड ज्याज के प्रश्न का जय स्पष्ट था और वह इस सवमाय परम्परा से पैदा होता था कि इंग्लैण्ड के मुख्य 'यायाधिपति' पद के लिए पहली तरजीह एटर्नी जनरल को मिलती है।

एच जी हैनबरी ने अपनी पुस्तक 'इंगलिश कोर्ट्स आफ ला' (इंग्लैण्ड के यायालय) में इस प्रणाली का वर्णन इस प्रकार किया है

लाड चीफ जस्टिस (मुख्य 'यायाधिपति') की नियुक्ति अन्य 'यायिक' नियुक्तियों से भिन्न होती है। वह प्रधान मंत्री के हाथ में है और जब वह पद रिक्त होता है तो पार्टी व्यवस्था की प्रथाओं के अनुसार इस पर दावा एटर्नी-जनरल के पक्ष में जाता है जो सम्राट का मुख्य 'यायिक' सलाहकार होता है और मंत्रिमण्डल का प्रमुख सदस्य भी होता है हालांकि आम तौर पर वह मंत्रिपरिषद (कबिनेट) का सदस्य नहीं होता। (पृ १६४-६५)।

किंतु लायड ज्याज, हेवट को खोना नहीं चाहते थे क्योंकि, उनके अपने ही शब्दा में, हेवट उनके लिए "परम आवश्यक" थे। हेवट बड़े प्रतिभाशाली सदस्य थे और लायड ज्याज लोक सभा (हाउस आफ कॉमन्स) में अपने दल के उपनेता के रूप में लगभग उन पर ही भरोसा करते थे।

कुछ समय तक लायड ज्याज ने फैसला स्थगित रखा, लेकिन अन्ततः मामला मिर तक आ गया क्योंकि लॉर्ड रीडिंग को भारत का वाइसराय बना कर भेजने का फैसला किया जा चुका था। फिर भी प्रधान मंत्री महोदय हेवट को "यायालय में भेजने के लिए राजी न थे और इसलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसके अनुसार "यायाधीश ए टी लॉरेंस ने, जिन्होंने वाद में लाड ट्रेवेथिन की पदवी ग्रहण की, मुख्य "यायाधिपति का पद इस वायदे के साथ सभाला कि ज्या ही सदन के भंग होने का समय आ जायगा, वह पद से इस्तीफा दे देंगे और हेवट के लिए रास्ता साफ कर देंगे। कुछ समय बाद ही जब लोक सभा भंग की जाने वाली थी तो लायड ज्याज ने विविध रीति से हेवट को दिया गया अपना वायदा निभाया, जिसका वणन हेवट की जीवनी के लेखक रॉयट जैकसन ने इस प्रकार किया है

लेकिन लायड ज्याज ने मूल इकरार पूरा किया। बिना किसी समारोह के परित्यक्त ट्रेवेथिन ने स्वयं अपने इस्तीफे का समाचार टाइम्स अखबार में पड़ा, और "यायाधिन" के सार्वाधिक सम्मानजनक स्थायी "यायिक" पद पर आसीन होने हुए हेवट ने वाचन वष की जायु में अपने जीवन की महत्वाकांक्षा पूरी की।^१

इस तरह स्पष्टतः इंग्लैण्ड में "यायाधीश" के सचयन में वरिष्ठता या पदोन्नति का कोई वास्तविक ध्यान नहीं रखा जाता।

आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया में "यायिक" ढाँचे में एक और उच्चतम राष्ट्रमण्डल "यायानय, आस्ट्रेलिया का उच्च "यायानय है तो दूसरी ओर राज्या में सर्वोच्च "यायालय है।

१९०३ और १९६५ के बीच आस्ट्रेलिया में सात मुख्य "यायाधिपति नियुक्त किये गये थे। मुख्य "यायाधिपति नियुक्त होने से पहले इनमें से दो प्रतिनिधि सभा (जो हमारी समझ की तरह है) के और मंत्रिमंडल के सदस्य

१ रॉयट जैकसन की पुस्तक 'दि चीफ', पृ. १४४

थे। एक व्यक्ति 'यायाधीश' नियुक्त होने से पहले प्रतिनिधि सभा का सदस्य और मंत्री था हालांकि बाद में उसे मुख्य 'यायाधिपति' के पद पर पदोन्नति दी गयी। दो अन्य सदस्य मुख्य 'यायाधिपति' बनने से पहले राज्या की विधान सभाओं के सदस्य थे और इन दोनों में से एक राज्य सरकार में मंत्री भी रहा था।

इसलिए यह स्पष्ट है कि मंत्री पद पर रहने समेत किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध होना उच्च 'यायिक' पद के लिए कोई बाधा नहीं है। आस्ट्रेलिया के वर्तमान मुख्य 'यायाधिपति', बारबिक, मुख्य 'यायाधिपति' नियुक्त होने से पहले केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में मंत्री थे और १९६४ में अपनी नियुक्ति के बाद नौ वर्षों से वह 'यायिक' पद पर हैं। उनके फैसलों का आस्ट्रेलिया में और बाहर सम्मान होता है तथा कोई उन्हें इसलिए सदेह की दृष्टि से नहीं देखता कि वह 'यायालय' में राजनीतिक क्षेत्र से आये हैं।

जहाँ तक उच्च 'यायालय' के 'यायाधीशों' की नियुक्ति की स्थिति है वह भी बहुत भिन्न नहीं है। १९०३ और १९६५ के बीच आस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय में १७ 'यायाधीश' (उपरोक्त मुख्य 'यायाधिपति' की नियुक्ति के अतिरिक्त) नियुक्त किये गये जिनमें से नौ व्यक्ति सीधे राजनीति से आये प्रतीत होते हैं। 'यायाधीश' पद पर अपनी नियुक्ति से पहले इनमें से सात व्यक्ति राज्यों की विधान सभाओं के या प्रतिनिधि सभा के सदस्य थे और तीन केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे जिनमें से एक तो 'यायाधीश' के पद पर नियुक्ति से पहले प्रधान मंत्री रह चुका था।

'यायाधीश' वाटन राजनीति में एक लम्बे और प्रतिभा-सम्पन्न जीवन के बाद—जिसमें वह विधान सभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, राज्य में मंत्री और फिर प्रतिनिधि सभा के सदस्य और प्रधान मंत्री तक रह चुके थे—१९०३ में 'यायालय' में नियुक्त किये गये थे।

इसलिए यह प्रकट है कि आस्ट्रेलिया में लम्बे और प्रतिभा-सम्पन्न राजनीतिक जीवन को 'यायाधीश' के पद पर नियुक्ति के लिए एक अयोग्यता के बजाय योग्यता माना जाता रहा है और फिर इंग्लैण्ड की ही तरह दस के उच्चतम 'यायिक' पद पर नियुक्ति के प्रश्न पर बरिष्ठता (सीनियोरिटी) का प्रश्न कभी नहीं उठा।

कनाडा

कनाडा का अनुभव भी आस्ट्रेलिया के अनुभव से भिन्न नहीं है।

अगर हम १९४७ और १९६० के बीच प्रान्तीय और सघीय स्तरों पर 'यायिक' पदों की नियुक्तियों की स्थिति को देखें तो इन बीच ४४ नियुक्तियाँ

की गयी थी। इनमें से पञ्चवीम के सुविदित राजनीतिक सम्प्रदाय थे और २२ व्यक्ति निर्वाचित राजनीतिक पदों पर रह चुके थे जिनमें से कई प्रांतीय मन्त्रिमंडलों में भी रहे थे। इनमें में पांच इस कान में प्रमुख राजनीतिक पदों पर रह चुके थे, जिनमें से चार व्यक्ति सघीय मन्त्रिमंडल में मंत्री रह चुके थे और एक प्रान्तीय मुख्य मंत्री। तीन अन्य व्यक्ति १९४० से पहले प्रांतीय मंत्री थे, जिनमें से एक व्यक्ति सघीय मन्त्रिमंडल में मंत्री भी रह चुका था।

यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन ४४ नियुक्त 'यायाधीशों' में से २१ व्यक्तियों को कोई भी पिछला 'यायिक' अनुभव नहीं था। इस तरह स्पष्ट है कि जहाँ तक कनाडा का सम्प्रदाय है, वहाँ 'यायिक' सापान में ऊपर चढ़ते चले जाने का कोई चित्र नहीं मिलता। उन २३ के मामले में भी जिन्हें पहले का 'यायिक' अनुभव था, गति की दिशा थी—अपील 'यायालय' से प्रांतीय सर्वोच्च 'यायालय' की ओर, फिर प्रान्तीय मुख्य 'यायाधिपति' के पद की ओर, या कनाडा के उच्चतम 'यायालय' की ओर।

४४ नियुक्त व्यक्तियों में से १७ ने कनाडा के उच्चतम 'यायालय' में काम किया। तब भी यहाँ पर १७ में से १० 'यायाधीशों' को पूर्व अनुभव के बिना ही, सीधे उच्चतम 'यायालय' में नियुक्त किया गया जब कि सात उ श्रुद्ध समय तक प्रांतीय 'यायालयों' में काम किया था।

कनाडा की 'याय' व्यवस्था के एक टीकाकार ने लिखा है कि, "यायिक पद राजनीतिक जीवन रेखा का अन्तिम बिंदु है।"

इस मामले की एक और दृष्टिकोण से परीक्षा करना दिलचस्प है। सन्यासमय हिसाब किताब यह है कि १९४०-६० के काल में १२१ व्यक्ति श्रुद्ध समय तक सघीय मन्त्रिमंडल में मंत्री या प्रांतीय मुख्य मंत्री पद पर रह और १९६२ में उनमें से ३० व्यक्ति तब भी इन पदों पर थे।

अगर प्राचीन बचे ६१ व्यक्तियों (१२१ में से ३० कम) को लें तो हम पायेंगे कि उनमें से १४ यानी लगभग छठवा भाग, 'यायिक' पदों पर थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजनीतिक जीवन के अंत से अक्सर न्यायिक जीवन शुरू हुआ। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कनाडा में राजनीति और 'यायालयों' के पदों के बीच कोई बहुत स्पष्ट जोर पंनी विभाजन रेखा रही है बल्कि एक जीवन बिना किसी बाधा के हमारे में उहना चला जाता है।

इस सारे मामले में कनाडा के अभिगम को नायद कनाडा की लोक सभा में एक प्रमुख सम्प्रदाय द्वारा दिये गये उस मापदण के उद्धरण में समझा जा सकता है जो १९६७ में एक वाद विवाद के बीच दिया गया था जब कि न्यायपालिका में राजनीतिक नियुक्तियों के प्रश्न पर बहस चली थी।

वहस में मि वूलियम्स ने विचार प्रकट किया था

में उन माननीय सदस्य से सहमत ॥ जिन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति जिसने सावजनिक जीवन में सेवा की हो, उसको इस तथ्यवश 'यायालय' में नियुक्ति के योग्य नहीं माना जाना चाहिए। इस सिलसिले में मैं मदन के एक भूतपूर्व सदस्य का किंचित सम्मानपूर्वक हवाला देना चाहूंगा, जो उस समय अपील कोर्ट में साम्राज्ञी की बेंच डिवीजन के सदस्य थे (अब उनकी मृत्यु हो चुकी है)। वह न सिर्फ अत्यंत योग्यता-सम्पन्न थे, बल्कि 'सार्वजनिक' जीवन में तथा जनता से व्यवहार करने में अपने अनुभव के कारण उन्होंने 'यायाधीश' के रूप में एक मानवतावादी दृष्टिकोण जोड़ा। इसलिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तथ्यवश कि एक व्यक्ति ने प्रान्तीय विधान सभा, लोक सभा या सावजनिक क्षेत्र में सेवा की है, उसको 'यायाधीश' पद पर नियुक्त किये जाने से रोक दिया जाना चाहिए। ऐसी सेवा को 'यायमत्री' को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि अगर एक व्यक्ति का अपने घर में, अपने मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ है तो हम विश्वास कर सकते हैं कि वह अच्छा 'यायाधीश' बनेगा और वह फैसले करने में तथा उनका दी गयी जिम्मेदारियों को निभाने में मानवीय होगा।

लेकिन शायद उच्चतम 'यायालय' में नियुक्तियों के सम्बन्ध में कनाडियाई दृष्टिकोण का सर्वोत्तम सार प्रस्तुत किया है मक्विनी ने अपने लेख 'कनाडा में 'यायालय' में नियुक्तियों का एक आधार' जो कनाडियन थार रिव्यू नामक पत्रिका के अंक ३३ (१९५५) में पृष्ठ ६७६ पर प्रकाशित हुआ है। उन्होंने लिखा

क्या शायद यह तथ्य कि 'यायपालिका' में सम्भावित नियुक्ति के लिए प्रस्तुत व्यक्ति सत्तारूढ़ पार्टी के साथ राजनीति में सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध था, उसको यायिक जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए किसी कदर कम योग्य बना देता है? जिन 'यायालयों' में नियुक्तियों की जाती हैं, उनके आधार पर शायद विभेद किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कनाडा के उच्चतम 'यायालय' को अक्सर सावजनिक कानून के मामलों पर फैसले देने होते हैं और इसलिए शायद उस 'यायालय' के सदस्यों को भारी लाभ होगा अगर उन्हें सावजनिक मामलों का अनुभव हो। १९५५ में अपनी नियुक्ति के पहले 'यायाधीश' एवट उस समय लिबरल पार्टी की सरकार

मे वित्त मंत्री थे और उन्हें सावजनिक मामले निबटाने के लिए मूयाय्य माना जाता था। दूसरी ओर काउंटी 'यायालयों के 'यायाधीशों को इस प्रकार के मामलों पर शायद ही कभी फंसला देने को कहा जाता है, इसलिए उन 'यायालयों में सावजनिक जीवन में अनुभव प्राप्त लोग को नियुक्त किये जाने का औचित्य कम है।

इसलिए उच्च 'यायिक नियुक्तियाँ के प्रश्न पर गम्भीर विचार विनिमय इस बिन्दु से प्रारम्भ होना चाहिए कि राजनीतिक जीवन तथा न्यायिक जीवन के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा का होना जनताधिक व्यवस्था का मूल तत्व नहीं है। इसके विपरीत आम तौर पर चार बड़े अंग्रेजी भाषी जनतन्त्रों में राजनीति, विचारधारा, व्यक्ति के दृष्टिकोण को उच्चतर 'यायिक सोपान पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करने में निर्णायक माना जाता प्रतीत होता है।

विन्तु अपने देश में हम सोझी दर-सोझी बानी दृष्टि द्वारा पूरी तरह दनदन में फस गये मालूम होते हैं। स्पष्ट ही यह उस अवशेष का परिणाम है जिस समस्या के प्रति सिविल सर्वेंट्स का रवैया और समझदारी कहा जा सकता है। सोपानवाद इंडियन सिविल सर्विस के ढांचे का मूल तत्व था और अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। और जिस ढंग से सिविल सर्विस में ऊपर की ओर चढ़ाव आम तौर पर वरिष्ठता (सिनियोरिटी) से निर्धारित किया जाता है, वही से 'यायिक प्रशासन की हमारी व्यवस्था में लागू किये जाने वाला सिद्धांत निकलता प्रतीत होता है।

अथ दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों के अतिरिक्त इसी से एक कलजलून स्थिति यह पैदा हुई है कि उच्चतम 'यायालय के काम की २३ वष जैसी छोटी सी अवधि में हमारे यहां १४ मुख्य 'यायाधिपति हुए—किसी अन्य देश में इसका समा नातर उदाहरण नहीं मिलता। अन्य देशों के तुलनात्मक आंकड़े ये हैं

ऑस्ट्रेलिया	७ मुख्य 'यायाधिपति	७० वर्षों में
कनाडा	१० मुख्य 'यायाधिपति	७३ वर्षों में
अमरीका	११ मुख्य 'यायाधिपति	१७३ वर्षों में
ग्रेट ब्रिटेन	८ मुख्य 'यायाधिपति	७३ वर्षों में

इसी का परिणाम है कि कुछ मुख्य 'यायाधिपतियाँ न एक महीने जैसी छोटी सी अवधि ('यायाधीश शाह) तक ही पद संभाला और चार वष से अधिक किसी ने नहीं। काई 'यायाधीश 'यायालय पर संशक्त और सवारात्मक प्रभाव छोड़े, उसकी अच्छा नेतृत्व और दृष्टिकोण सम्बन्धी निरंतरता दे तथा

उचित परम्पराएँ डाले, इसके लिए सामान्यतः यह अवधि बहुत कम है। यहाँ हम फिर अमरीका के उदाहरण से लाभ उठा सकते हैं जहाँ १९५२ से १९६८ तक 'यायालय' को वारेन-न्यायालय कहा जाता है—एक ऐसा 'यायालय' जिसने मुनिदिष्ट रूप से उदात्तपथी प्रवृत्ति के फैसलों से, विशेषकर जातिभेद तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सम्बन्ध में फैसलों से, एक बीतिमान स्थापित किया।

इस दृष्टि से भी वरिष्ठता के आधार पर 'यायाधीश' को नियुक्त करने के अमल या रिवाज का 'यायालय' को काय प्रणाली पर निश्चय ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

५. अमरीकी उच्चतम न्यायालय और “नव व्यवहार” नीति

अमरीका में “नव व्यवहार” (नू डील) नीति के बाल में कायपालिका और पापपालिका के बीच टकराव की घटना चायद एग्लो-सैंक्सन दुनिया के पापालयो के इतिहास में सर्वाधिक नाटकीय है।

अमरीका के श्रेष्ठतम राष्ट्रपतिया में से एक, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ने १९३२ में डेमोक्रेटिक पार्टी की तूफानी विजय में, जिसमें ससन् में भी डेमोक्रेटों का बहुमत मिला, ह्वट हूवर के विरुद्ध भारी विजय प्राप्त की थी। चुनाव का केन्द्रीय प्रश्न या आर्थिक मंदी की समस्या जो १९२९ में सट्टा बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) के ढह जाने के बाद शुरू हो गयी थी। रूजवेल्ट जनता के पास यह साहसी और मुनिश्चित वादा लेकर गये कि वह देश को मंदी के कुप्रभावा से मुक्त करने के लिए तेजी से कदम उठावेंगे।

रूजवेल्ट नवम्बर १९३२ में चुने गये और जनवरी १९३३ में उन्होंने कामभार सभाला। तुरन्त उन्होंने अपना “नव व्यवहार” कार्यक्रम शुरू किया जिसमें अत्यन्त आवश्यक आर्थिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से कई कानूनीकारी क़दम थे। इस कार्यक्रम की सर्वधानिक वैधता थी जिसको उच्चतम पापालय में चुनीती दी गयी और एक आर राष्ट्रपति तथा दूसरी ओर

न्यायालय के बीच सम्भाव्य संधर्ष इन कानूनों की मविधान-सम्मतता के गिद उठ खड़ा हुआ ।

उस समय के अमरीकी उच्चतम न्यायालय में नौ न्यायाधीश थे । और जब नव व्यवहार कानून न्यायालय के सामने आये तब रुडिपथी और उदारपथी न्यायाधीशों के बीच विभाजन लगभग बराबर था । यह समझ लिया गया था कि चार रुडिपथी सदस्य, न्यायाधीश गण जेम्स मैक्रेनोल्ड्स, पियस बटलर, जॉर्ज सदरलैंड और विलिस वान डिवेटर नव व्यवहार के विरुद्ध वोट देगे । इनसे से हर न्यायाधीश अथनीति में मुक्त व्यापार दशन के और राजनीतिक क्षेत्र में संधीय सरकार के सीमित अधिकार की नीति का अनुयायी था । इसके विपरीत उदारपथी न्यायाधीश गण—लुई डी ब्राडइस, हारलन एक स्टोन और बेंजामिन एन कार्डोजो—भी अपन दृष्टिकोण में सुरक्षित तथा नव व्यवहार कार्यक्रम में सहानुभूति रखत थे । और इनके बीच सन्तुलन सभालने वाला थे मुख्य न्यायाधिपति हूजेस और न्यायाधीश ओवेन ज रॉबट्स । इन दो न्यायाधीशों ने रुडिपथी सेमे से अपनी धुम्मात की थी, मगर बाद में १९३६ में रुजवेट के पुन निर्वाचित होने के बाद अपनी स्थिति बदल ली ।^१

रुजवेट के सत्तापुंड होने के सुरान बाद १९३३ में मसद द्वारा नव व्यवहार कानून पास कर दिये गये थे । मगर व अदालत में चुनौती के लिए पेश किये गये १९३५ में और छ महीने में न्यायालय ने दस बड़े मुकदमा में फैसले दिये । न्यायालय न दस महत्वपूर्ण मुकदमा में से आठ की अवैध करार कर देने वाले फैसले दिये और अमत में रुजवेट के कार्यक्रम का सारनव नष्ट कर दिया । उनमें ममश राष्ट्रीय औद्योगिक पुनर्जीवन कानून, स्वयं राष्ट्रीय पुनर्जीवन कानून, रलरोड पेंशन कानून, सेत रेहननामा कानून, कृषि समजन कानून, विद्वमिनस कोयला कानून और म्युनिसिपल दिवालियापन कानून का रद्द कर दिया ।

उन न्तिा के एक टीकाकार न इन कानूनों का अवधानिक घापित करने के विषय में कहा था

घापिक सत्ता और लोअपिय सत्ता के बीच बुनियादी खाइ का छिपाना या धनदसा करना अब सम्भव नहीं रह गया था । एव छाट से सत्र में

१. जिन नार न्यायाधीशों ने नव व्यवहार का लगातार निरोध लिया और उससे नष्ट करने का प्रयत्न किया यानी बर्नर मैग्नेनोल्ड्स वान डिवेटर और सदरलैंड, तथा राबर्ट्स नि दोने उनके साथ काम पुरू किया था और बाद में पक्ष बदल लिया
५. उनसे पिछले जीवन का विवरण परिशिष्ट २ में दक्षिण

“यायालय ने राजनीतिक सत्ता के हाथ पाव बाधने के लिए सभी स्तरों पर एक बड़ा सर्वधार्मिक जाल बुन दिया था। १९३६ के वसंत काल तक ऐसा लगता था कि “यायालय ने नव व्यवहार को असर्वधार्मिकता के छिछले तट और चट्टानों पर पटक कर चूर चूर कर दिया है।”

१९३६ में रूजवेल्ट पुनः मतदाताओं के सामने गये। सारे अव्वारों ने भविष्यवाणी की कि वह हार जायेंगे और उनका विरोधी जीत जायगा। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में जो दुर्गन्धी और जगन्नामी बदम प्रस्तावित किये थे, उनकी यह कह कर निंदा की गयी कि उनसे समाज में टूट फूट पैदा होगी और अमरीका बरबाद हो जायगा। फिर भी सभी बड़े अव्वारों के लगभग एकमत विरोध और उनके इस मूल्यांकन के बावजूद कि रूजवेल्ट निश्चय ही हारेंगे, उन्होंने आश्चर्यजनक और बिनाल बहुमत से विजय पायी तथा दो राज्यों को छोड़ कर दोष सभी राज्यों तथा मतदाताओं में ६० प्रतिशत का समर्थन प्राप्त किया।

तुरंत १९३७ की कांग्रेस में उन्होंने मुप्रसिद्ध “यायालय के पुनर्गठन का कानून” पेश किया जिसका उद्देश्य संघीय “यायपालिका” में आमूल परिवर्तन करना था।

विधेयक में उच्चतम “यायालय” के “यायाधीशों” के लिए ७० वर्ष की आयु में स्वेच्छा से अवकाश प्राप्त करने की व्यवस्था थी। उसमें नियम रखा गया कि अगर “यायालय” का प्रत्येक सदस्य, जो आयु सीमा पर पहुँच जायेगा और अस्काश प्राप्त नहीं करेगा, तो राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह एक अतिरिक्त “यायाधीश” नियुक्त करे। “यायाधीशों” की अधिकतम संख्या १५ निर्दिष्ट की गयी। अपने प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए रूजवेल्ट ने कहा था

यायिक व्यवस्था में कृतापूर्वक और लगातार नया और नौजवान खून लाने से, मुझे सचप्रथम आभा है कि संघीय “यायपालिका” के प्रशासन को तीव्रतर और इसलिए कम महंगा, बनाया जा सकेगा, दूसरे, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर फैसले लेने के लिए नौजवान लोग लाये जा सकेंगे जिनका ऐसे आधुनिक तथ्या तथा परिस्थितियों का व्यक्तिगत अनुभव और सम्पर्क है जिनमें औसत आदमी को रहना और काम करना

१ दक्षिण अटलैन्स टी मेसन की पुस्तक ‘दि मुपीम वोट बेहिनल ऑफ रिवाइंड ट्रुथ और पावर ग्रुप’ १९३०-३७ पृष्ठ ३६-३७

पड़ता है। यह योजना हमारे राष्ट्रीय संविधान की 'यायिक' नाड़ियों को जड़ोभूत होने से बचा लेगी।^१

रूजवेल्ट के इस प्रस्ताव से उन्हें तुरन्त छ नये 'यायाधीश' नियुक्त करने का अधिकार मिल जाता क्योंकि उच्चतम 'यायालय' के नौ 'यायाधीशों' में से छ अभी ही सत्तर वर्ष की आयु पार कर चुके थे। इस तरह राष्ट्रपति को उदारपथी दार्शनिक दृष्टिकोण वाले 'यायाधीश' नियुक्त करने की छूट मिलनी जो 'यायालय' में उस समय पदासीन अल्पमत उदारपथी 'यायाधीशों' जैसा दृष्टिकोण अपना सकते और ईमानदार तथा साहसी नेतृत्व दे सकें। अब यह आश्वासन करने का रास्ता खुल गया था कि 'यायालय' में उदारपथ का निर्णायक बहुमत होगा जो निश्चय ही नव व्यवहार के मुख्य फौसला को वंचित कर सकेगा।

रूजवेल्ट की योजना से पूरे अमरीका में एक ओर समाचारपत्रों की तरफ से और दूसरी ओर वकीलों के संगठनों की तरफ से व्यापक विरोध उठ खड़ा हुआ। 'यायालय' की हठधर्मी और प्रगतिशील कानूनों का अवैध करार देने के उमकें इरादों के कारण जो बंठिन समस्याएँ पैदा हो गयी थीं उनको हल करने के लिए राष्ट्रपति ने जिस प्रकार स्पष्टतावादी रूप में और ईमानदार तरीके से कदम उठाया था, उमको रूढ़िवाद के ये परम्परागत गढ़ बर्दाश्त न कर सके।

प्रश्न इतना ही नहीं है कि जब 'यायाधीशों' के सामने प्रस्तुत प्रश्नों पर फैसले दिये जाने हैं तब वे विवेक और तर्कबुद्धि का उपयोग करते हैं। यह फैसला हुआ कि नौ में से चार 'यायाधीशों' ने लगातार, और एक बार भी भटके बिना, एक ही पक्ष में, यानी नव व्यवहार कानून के विरोध में, वोट दिया, और इसी प्रकार लगातार तीन अन्य विद्वान 'यायाधीशों' ने दूसरे पक्ष में, यानी नव व्यवहार कानूनों को वंच मानने के लिए वोट दिया? कोई भी इतना तर्कहीन नहीं होगा कि वह 'यायाधीश' ब्रूडेल, स्टान और कार्डोन्जा पर सरकार का अनुपहार होने का आरोप लगाये। और मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि रूढ़िपथी 'यायाधीशों' ने जो स्थितिया अपनायी, वे इसलिए थीं कि वे 'यायाधीश' किमो व्यक्तिगत तरीके से, किन्हीं असंगत या अप्रामाणिक कारणों से, बायपासिंग के विरोधी थे। 'यायालय' में विनाशजन 'यायाधीशों' के मौलिकता में विभाजन से पैदा हुआ था। एक तरफ वे लोग थे जो रूढ़िवादी थे जिनका अगर सचमुच आग जलने में कोई विश्वास था तो धीरे धीरे आगे बढ़ने में ही और उन्हें हारि

कता तथा ईमानदारी ने यकीन था कि रूजवेल्ट के उग्र कार्यक्रम में अमरीका पर विपत्ति का पहला दृढ़ पड़ेगा, और दूसरी ओर उदारपंथी थे जिनका विश्वास था कि देश को जिस रास्ते पर जाना चाहिए इसकी दिशा और व्यापक नीतियाँ निर्धारित करना मताच्छेद पार्टी का काम है और उन्हें उन करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं से हमदर्दी थी जिन्होंने रूजवेल्ट को सत्ताच्छेद बनाया था।

दो बड़े फैसलों की जरा विस्तार से परीक्षा करना लाभदायक होगा।

पहला फैसला था कृषि समझन कानून के विषय में। यह कानून मगद ने कृषि के लिए आने वाली कृषि उपजों की सम्पत्ति कम कर उम्र कीमत को बढ़ाने के लिए पास किया था जो सेनिहुर अपनी फसल तथा अन्य उपजों के लिए पा रहे थे। इस उद्देश्य से, अमल में सरकार ने किसानों का काम अनाज पैदा करने के लिए एक विश्वस्त दी थी ताकि ऐसे फलतः भण्डार न बच रहें जिनके कारण खेती की जिंदा की कीमत कम रहनी थी। इन सहायता कार्यों के लिए दी जाने वाली रकम एक उत्पादन शुल्क से आनी थी जो सेनिहुरों पर नहीं, उन खाद्य सामग्री निर्माताओं पर लगाया गया था जो खेती की उपज का, प्रथम चरण में, खाद्य-सामग्री बनाने के लिए हाथ में लेते थे। स्वाभाविक था कि खाद्य सामग्री निर्माता नये कर के विरुद्ध थे और उन्होंने इस कानून की सर्वप्रधानता को चुनौती दी। और खाद्य निर्माताओं का वकील जॉर्ज व्हाटन पेप्पर ही था जो एक समकालीन टीकाकार के शब्दों में "पायालय के सामने वेस्पियन सिपाही की तरह रोमांच था" और कहा था

मैं भव्यतम भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि स्वतंत्र लोगों की भूमि के स्थान पर श्रृंखलाबद्ध लोगों की भूमि को एक सुयोग्य प्रनिराधन के रूप में मेरे जीवन बाध में स्वीकार न किया जाय।

शायद यही सम्भाषण था जिसमें प्रेरित होकर उच्चतम पायालय में हाल के सविधान सशोधन सम्बंधी मुकदमे में वादी की ओर से मुख्य वकील ने अनगिनत सम्भाषण दिये और चेतावनी दी कि अगर सरकारी पक्ष का मत माना गया तो भारत पतन और विनाश के गत में पहुँच जायगा।

उपरोक्त कृषि समझन कानून को रद्द करने वाले बहुमत के फैसले को न्यायाधीश राइट ने सुनाया था जिसने उस कानून को अवैध करार देने के लिए एक बड़ा मामला आधार दिया था अर्थात् यह कि कांग्रेस (संसद) को कर लगाने और आम लोक कल्याण के लिए उसकी सच करने का अधिकार है, मगर वह कर लगाने के अधिकार का इस प्रकार उपयोग नहीं कर सकती कि जिससे कृषि उपज का नियमन और उन नयन करने के सम्बंध में राज्यों के अधिकार

म हस्त-नेप हो क्याकि यह एकान्तिक रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है, सध सरकार के क्षेत्र में नहीं।

उस मामले में अल्पमत के फँसले को मुनात हुए 'यापाधीश' स्टोन ने ही एक ओर कायपालिका तथा ससद और दूसरी ओर 'यापालय' की काय प्रणाली के विषय में उदार दृष्टिकोण का सार अत्यन्त स्पष्ट रूप से पेश किया था।

'यापालय' ही सरकार की एकमात्र ऐसी एजेंसी नहीं हैं जिनकी शासन-समता को मान लेना चाहिए

और

शक्ति के हमारे द्वारा उपयोग पर एकमात्र प्रतिबन्धन है तो हमारी अपनी आरम्भ समय की भावना।

इसलिए स्टोन ने टीका की

यह सुझाव कि उसमें (सरकार की कायपालिका सम्बन्धी शक्ति में जिसका कि वह अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करती है) अब 'यापिक' आन्तर द्वारा कटौती करनी होगी क्याकि उसके अविवेकपूर्ण उपयोग द्वारा उसका दुरुपयोग हो सकता है तब की सम्मानजनक नहीं बना सकता। इसी प्रकार 'यापिक' शक्ति का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकार सम्बन्धी हमारे महान चाटर की व्याख्या अगर किसी ऐसी पूर्वधारणा के अनुसार की जाती है कि हमारी सत्स्था का भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की तीन शाखाओं में से किसी एक की एवान्तिक चिन्ता का विषय है या एकमात्र वह ही उसको विनष्ट होना से बचा सकती है तो दोष अधि में अधिन सम्भव यही है कि उससे 'अविनाशी राज्य की एक अविनाशी व्यष्टि' के निर्माता सत्स्था का सफाया हो जाय—बजाय इसके कि स्पष्टतावादी रूप में वह माना जाय कि भाषा एक मन्त्रिधान तन्त्र की भाषा का अर्थ वही हो सकता है जो वह कहता है।

दूसरा उदाहरण उस तौर तरीक़ का है जिसके जरिये एक और जीवन-मय व्यवहार कानून विद्वानों कायना कानून को अवैध बनाने के लिए साधित बीटा (निपयाधिकार) का उपयोग किया गया था इस कानून से

उस बीमार उद्योग में उत्पादन, बीमारी और बेरोज़गारी का नियमन इस प्रकार किया गया था कि इस कानून का सधु राष्ट्रीय उद्योग पुनर्जीवन कानून कहा जाता था जिससे भी व्यापार्य ने रद्द कर दिया था। यह कानून जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया था, यानी एक तेज उद्योग को नियंत्रित करना जो सर्वांगत बीमार था, उसमें विषय में यह सटीक और सुस्पष्ट था। और स्वाभाविकतया जो बीयला व्यवसायी बायला गान उद्योग को तोड़ने कोशिश करने के लिए हर प्रयत्न कर रहे थे, वे इसने बहुत विरोधी बन गए।

यह नोट करना दिलचस्प है कि व्यापार्यीय सदरलैण्ड ने, जिन्होंने इस तरह व्यवहार कानून को अर्थ करार देने का बहुमत पंक्ती गुणा था, इस कानून का पणन करने में "कुस्मिन्" और "अवाधनीय" जैसे शब्दों का उपयोग किया था, हालांकि अन्ततः उसका अर्थ करार दिया गया था एक विपुल विचार्य आधार पर, यानी कि उसमें "अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य" की धारा का उल्लेख होता था।

यह नोट करना भी दिलचस्प है कि अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य की यह धारा हड्डानी बीयला गान मजदूरों को जेल की सजा देने वाले सघीय व्यापार्यीय का रोने के लिए कभी आधार नहीं बनायी गयी। हालांकि बीयला पैदा करने वाले हर प्रमुख राज्य ने कानून के समर्थन में अपने बयान दिए और अनुरोध किया कि इस मामले को हज़रत का अधिकार राज्या के हाथ में सौंपने के बजाय उस पर राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रण करना या अधिकार दिया जाय तब भी इन सभी प्रायनात्रा के बावजूद व्यापार्यीयों के बहुमत ने घोषणा की कि बीयला गान उद्योग "एक स्थानीय व्यापार" है और इसलिए 'सघीय नियमन राज्यों के अधिकारों पर एक हमला है।"

यह स्थिति की १९३६ के प्रारम्भ में। राष्ट्रपति पद के चुनाव का अगला दौर आन बाना था जो नवम्बर १९३६ में होता था। और रज्जवेल्ट के विरोधियों ने अपने वायत्रम में हमले का मुख्य सूत्र रखा था सविधान के प्रति रज्जवेल्ट की अमानना जैसा कि व्यापार्य द्वारा अधिकांश तब व्यवहार कानून को नगानार और सुस्पष्ट रूप में बीटा किये जाने में प्रकट था। रज्जवेल्ट का विरोध करने और व्यापार्य को एक उच्च गिम्बर पर पहचान के उद्देश्य में "स्वतंत्रता सघ" के नाम में प्रतिनिधियों का एक सगठन समूह अमरीका में स्थापित किया गया था। इस स्वतंत्रता सघ का मुख्य वक्तव्य यह था कि एक ओर व्यापार्य जिसकी वे आसमान तक तारीफ कर रहे थे और दूसरी तरफ रज्जवेल्ट जिसकी निन्दा के लिए कैंने भी शब्द उन्हें काफी सशक्त नहीं लगते थे— इनके बीच सम्बंधों को चुनाव अभियान का केन्द्रीय मुद्दा बनाया जाय।

किन्तु शरट उस समय सचमुच उभर आया जब कि यूनाय द्वारा पास

किया गया मजदूरनियो के 'यूनितम वेतन सम्बन्धी कानून को 'यायालय मे चुनौती दी गयी ।

यह ऐसा कानून था जिसको डेमोक्रेटिक (रूजवेल्ट की) पार्टी तथा रिपब्लिकन पार्टी (जिसको अधिक रूढ़िवादी पार्टी माना जा सकता है), दाना का समर्थन प्राप्त था । उच्चतम 'यायालय ने इसको इस आधार पर रद्द किया कि इससे चौदहवें संशोधन, यानी इकरारनामे की स्वतन्त्रता, का उल्लंघन होता है ।

एक अर्थ मे 'यायालय के इस फैसले से सारे देश को धक्का लगा और जब डेमोक्रेटिक पार्टी के सम्मेलन मे रूजवेल्ट को हृषध्वनि के साथ नामजद किया गया, तब 'यायाधीशो पर आरोप किया गया कि उन्होंने नव व्यवहार का "तकनीकी सख्ती द्वारा और पुराने पड गये आर्थिक मनमानेपन को लागू करके ताक पर रख दिया है ।"

यही भावना थी जिसके साथ अमरीकी जनता ने नवम्बर १९३६ के चुनाव मे भाग लिया । चुनाव मे रूजवेल्ट को भारी बहुमत प्रदान किया गया जिसमे दो राज्यों, वरमोन्ट और मेन, को छोड कर अमरीका के सभी राज्यों ने उनका साथ दिया ।

इस विराट समर्थन से सशक्त होकर रूजवेल्ट जजा के किय को मिटाने का संकल्प लेकर फिर सत्ताहूड हुए । और इस बात को उन्होंने ६ मार्च १९३७ को अपनी जनता के नाम प्रसारित एक अत्यन्त स्फूर्तिप्रद भाषण मे स्पष्ट कर दिया । उस भाषण मे, जो पढने मे आज भी उतना ही सबल लगता है जितना कि ३६ वष पहले था उन्होंने घोषणा की

जन कांग्रेस (संसद) ने राष्ट्रीय वृषि को स्थिर बनाने, मजदूरों की हालत सुधारने अनुचित होठ से व्यापार की रक्षा करने, हमारे राष्ट्रीय साधनों को सुरक्षित बनाने तथा अन्य अनेक उपायों से स्पष्टतया राष्ट्रीय आवश्यकताएँ पूरी करने का प्रयत्न किया, तो 'यायालय का बहुमत कांग्रेस के इन कानूनों की विवेकनिष्ठता पर फमने देने और इन कानूनों मे लिखी गयी सावजनिक नीति को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार ग्रहण करने लगा है । यह सिर्फ मरा ही आरोप नहीं है । यह वर्तमान उच्चतम 'यायालय के अत्यन्त सम्मानित न्यायाधीशों का भी आरोप है । इन असहमतिभूलक मतों के सामने, 'यायालय के कुछ सदस्यों के इस दाव का कोई आधार नहीं है कि संविधान की किसी चीज ने उन्हें जनता की आराधना को बेदपूर्वक अवरोध करने के लिए विवश किया है । अपन 'यायिक कार्याधिकार का उचित उपयोग करने के अतिरिक्त 'यायालय ने

संविधान में ऐम शब्द और निहिनाथ पढ़ने हुए, जो उसमें नहीं है और जिनको वहाँ रखने का कभी किसी का इरादा भी न था, अपने को कांग्रेस के एक तीसरे सदन—एक महा सदन (सुपर सेजिस्लेचर), जैसा कि न्यायाधीशों में से एक ने कहा भी है—के रूप में अनुचित ही स्थापित कर लिया है। इसलिए हम एक राष्ट्र के रूप में एक ऐसे बिन्दु पर पहुँच गये हैं जहाँ हमें न्यायालय से संविधान को बचाने और न्यायालय को स्वयं उससे बचाने के लिए कायवाही करनी पड़ेगी। हम अपील को उच्चतम न्यायालय से स्वयं संविधान के सामने ले जाने का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम ऐसा उच्चतम न्यायालय चाहते हैं जो संविधान के मातहत—उसके ऊपर नहीं—ग्याय करेगा। अपनी अदालत में हम कानून की सरकार चाहते हैं, कुछ आदमियाँ की नहीं। मैं चाहता हूँ—जैसा कि सभी अमरीकी चाहते हैं—कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, जैसा कि संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावित किया था। इसका अर्थ है ऐसा उच्चतम न्यायालय जो संविधान का जैसा कि वह लिखा गया है उसी रूप में लागू करे और जो न्यायिक अधिकारों के मनमाने उपयोग द्वारा संविधान को संशोधित करने से—न्यायिक कथनी द्वारा संशोधन से—इनकार कर दे। इसका अर्थ ऐसी स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है कि वह सावधानीपूर्वक रूप से स्वीकृत तथ्यों के अस्तित्व तक को न माने। जो लोग इस योजना के विरोधी हैं, वे यह चीख पुकार मचा कर कि मैं उच्चतम न्यायालय को 'दफा करने' का प्रयत्न कर रहा हूँ और इससे एक विघातक दृष्टान्त बन जायगा पूर्वग्रह और भय जाग्रत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 'न्यायालय को दफा करने' शब्दों से उनका क्या मतलब है? इस प्रश्न का मुझे मुहफ़्त तरीके से जवाब देने दोजिए ताकि मेरे उद्देश्यों के विषय में ईमानदारी से पैदा हुई सभी गलतफ़हमियाँ खत्म हो जायें। अगर इन शब्दों से यह अभियोग लगाया जाता है कि मैं न्यायालय में ऐसे लोग बैठाना चाहता हूँ जो बरीद बठपुतलियाँ की तरह होंगे, जो कानून की अवहेलना करेंगे और खास मामला पर जैसा मैं चाहूँगा वैसा फैसला देंगे, तो मेरा जवाब यह है उच्चतम न्यायालय में इस विस्म के व्यक्तियों को न तो अपने पद के योग्य कोई राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है और न अपने पद के योग्य सम्मानित व्यक्तियों की सीनेट उनकी नियुक्ति की पुष्टि कर सकती है। लेकिन अगर इन शब्दों से यह अभियोग लगाया जाता है कि मैं न्यायालय के वर्तमान ऐसे सदस्यों के साथ, जो उन आधुनिक परिस्थितियों को समझते हैं, बैठने के योग्य न्यायाधीशों को नियुक्त करूँगा और सीनेट उनकी पुष्टि करेगी, कि मैं ऐसे न्यायाधीशों

को नियुक्त करूँगा जो कानून सम्बन्धी नीति पर कांग्रेस के नियम के विरुद्ध व्यवस्था देन का प्रयत्न नहीं करेंगे, कि मैं ऐसे 'यायाधीश' नियुक्त करूँगा कि जो 'यायाधीशों' की तरह काम करेंगे, कानून निर्माताओं (संसद सदस्यों) की तरह नहीं—अगर ऐसे 'यायाधीशों' की नियुक्ति को वे 'यायालय को दफा करना' कहते हैं तो मैं और मेरे साथ अमरीकी जनता का विश्वास बहुमत ठीक यही काम करेंगे—अभी ही।'

इन्दिरा गांधी ने बैंक राष्ट्रीयकरण कानून के साथ एक नयी प्रक्रिया—आर्थिक कार्यक्रम और कार्यवाही के लिए एक नया तथा अधिक उग्र चिन्तन—शुरू किया। और यहाँ भी, 'यायालय' ने उसको रद्द कर दिया।

उन्होंने पुरानी व्यवस्था के अवशेष रखाड़ों के खिलाफ एक आदेश जारी किया। 'यायालय' ने उसको भी रद्द कर दिया।

अमरीका में रूजवेल्ट ने १९३६ का चुनाव नब्दा और उस समय जिन मुख्य प्रश्नों में से एक पर जनता को फैसला देना था, वह था 'यायालय' के अधिकार और कार्यपालिका के अधिकार का प्रश्न। जनता ने निराशा की भविष्यवाणी करने वाले अनेक पैगम्बरों की इस चेतावनी के बावजूद कि रूजवेल्ट देश का महानाश की ओर ले जा रहे हैं रूजवेल्ट का वोट दिये।

इसी तरह भारत में १९७१ के आरम्भ में इन्दिरा गांधी चुनाव में उतरी और मुख्य प्रश्न में से एक था कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए या नहीं और क्या 'यायालय' द्वारा अवैध ठहराये गये कानूनों को नाबिधिय प्रथ में पुन शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। और यहाँ भी अनेक निराशावादियों ने, विनोदचर समाचारपत्रों में इन्दिरा गांधी की महापराजय की भविष्यवाणी कर दी फिर भी जनता ने काफी पैमाने पर समयन दिया और स्वतंत्रता के बाद से जितनी चुनाव जीतें देखने की मिस्री हैं उन सगस अधिक भारी तीन दो।

लेकिन जहाँ रूजवेल्ट ने अदालत का 'दफा करने' जमा अत्यंत उग्र और नातिनारी प्रस्ताव तब पंग किया तथा 'यायालय का दफा करने' के दम प्रस्ताव के लिए अपन समस्त समयका का अनुमान प्राप्त किया, वहाँ भारत में सिर्फ इतना ही हुआ कि तीन 'यायाधीशों' का अधिग्रहण किया गया और चौथे को जो हम सम्मानित यायाधीश है भारत का मुख्य 'यायाधिपति' नियुक्त कर दिया गया।

१. १ मार्च १९३७ को राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रचारित भाषण का अरत नेत्रि सौदागरी अमरीकी प्रसूक्त दिवास्मिन्मन लॉ ऑफ इंडिया', पृ. १०८८

निस्संदेह, "यायालय को दफा करने" सम्बन्धी रूजवेल्ट के प्रस्ताव का भी अमरीका की अधिक रुढ़िवादी गतिविधि की ओर स, जिनम सीनेट की "यायिक समिति और कई वकील सघ भी थे, विरोध के तूफान से स्वागत किया गया। किन्तु १९३६ में उनकी चुनाव विजय के बाद दो "यायाधीशों ने जो पहले उनके विरोधी थे (मुख्य "यायाधिपति हूजेस और "यायाधीश रायट्स), तीन उदारपथी "यायाधीश (ब्राडेइस, कार्डोजो और स्टोन) का साथ दिया और उनके सभी निर्णायक कानूनों को बँध कर दिया। स्थिति में इस परिवर्तन से "यायालय में उदारपथियों का बहुमत हो गया (६ में से ५) और इसमें रूजवेल्ट का प्रस्ताव अनावश्यक हो गया। किन्तु, अगर ऐसा न हुआ होता, तो इस संकट पर एक लेखक के शब्दों में

फिर भी तमाम शोरगुल के बावजूद राजनीतिक दबाव से योजना पास हो गयी होती अगर इस बीच हूजेस (मुख्य "यायाधिपति—मो कु) उन सबसे अधिक चालाक राजनीतिज्ञ न सिद्ध हो गया होता।^१

रूजवेल्ट के काल की उन तूफानी घटनाओं से क्या हमें भारत के लिए कुछ सबक नहीं निखालने चाहिए और क्या हम ये सबक नहीं निकाल सकते ?

१ स्पष्ट ही यहाँ इशारा दिया जा रहा है मुख्य न्यायाधिपति के उदारपथी पक्ष में शामिल हो जाने के विषय में उद्धरण है फ्रेड रोवेल की पुस्तक 'नाइन मेन' से पृ २४८

६ न्यायाधीशों का दर्शन

दो 'यायाधीशा, 'यायाधीश हंगे और 'यायाधीश राय के "दर्शन" में अंतर को समझने के लिए यह दिलचस्प होगा कि किन्हीं मूल प्रश्नों पर उनके विचारों की परीक्षा की जाय जो उनके हाल के फैसलों में व्यक्त हुए हैं।^१

पहले, आइए हम ससद की प्रभुसत्ता पर उनके विचारों को ले—इस प्रश्न पर कि अनुच्छेद ३६८ के मातहत संविधान में संशोधन के अधिकार का उपयोग करते हुए क्या ससद जनता की इच्छा की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है।

'यायाधीश हंगे अपने विचारों का इस प्रकार पेश करते हैं^२

हमने पहले देखा है कि हमारी चुनाव व्यवस्था के अन्तर्गत, अगर एक पार्टी चुनाव में डाले गये बाटों का सम्पूर्ण बहुमत न पा सके तब भी उसके लिए ससद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर लेना सम्भव है।

१ १९७२ की प्रादेश याचिका न १३५—वमाधिरान केगशनन्द भाग्यी बनाम केरल राज्य जिसका फैसला २४.४.१९७३ को सुनाया गया था।

२ म यदा उन्नेय वर द मि एफ ओर यायाधीश हंगे और दूसरी ओर यायाधीश राय तथा गोवर के विचारों में बहुत कम अंतर है इसलिए मैं अपने दो न्यायाधीश हंगे के विचारों तक सीमित रग रहा हूँ।

इस दाव का कि ससद सदस्यों का बहुमत या ससद के दो तिहाई सदस्य भी राष्ट्र की ओर से बोलते हैं, कोई तथ्यगत आधार नहीं है। वास्तव में मतदाताओं का विश्वास खो देने के बाद भी एक शामक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पास करा लेना सम्भव हो सकता है। लोक सभा के सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। शामक पार्टी या उसके सदस्यों को अपने पद की पूरी अवधि तक मतदाताओं का विश्वास प्राप्त रह सकता है, और नहीं भी रह सकता। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि जब भी ससद संविधान में संशोधन करती है, तो उसको जनता की इच्छा के अनुसार माना जाना चाहिए।

‘यायाधीश राय का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। पहले वह कहते हैं

संविधान में संशोधन करने वाला संगठन जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है।

अथवा वह यह भी टीका करते हैं

पहला और सबसे प्रमुख रक्षोपाय है विधानमण्डल का संवैधानिक और समुदाय का स्वयंभू संवैधानिक

और तब वह टीका करते हैं

नागरिक का चरित्र, विधानमण्डल का चरित्र, प्रतिनिधियों में जनता की आस्था और राष्ट्र के प्रति प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व—इनसे अच्छा दूसरा कोई रक्षोपाय नहीं है। जनता के प्रतिनिधियों पर कोई अनुत्तरदायित्व भावना मढ़ी नहीं जा सकती और न वह उनका दुगुण बतायी जा सकती है।

इस दो ‘यायाधीशों’ के दो बिल्कुल विरोधी दृष्टिकोणों से उनके अपने उपागम तथा दशन के बीच मूलभूत अन्तर तीखे और स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। एक ओर ‘यायाधीश’ कहते हैं वह भी मानने को तैयार नहीं कि ममद जनता की, या जनता की इच्छा तक की प्रतिनिधि है, दूसरी ओर ‘यायाधीश’ राय का स्पष्ट मत है कि ससद जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने पर ममद पर अनुत्तरदायित्व की किसी भावना का शेष नहीं मढ़ा जा सकता।

अपने विश्लेषणा में 'यायाधीन' हेगडे हमारे चुनाव व्यवस्था के मूल आधार को ही चुनौती दे बैठते हैं, 'जनता का प्रतिनिधि' होने के लिए यह कोई पूर्वावश्यकता नहीं है कि एक व्यक्ति को अपने चुनाव क्षेत्र में बहुमत वोट मिलें, आवश्यक है तो यह कि उसको सबसे अधिक सच्चा में वोट मिलें। यह बात उन सभी देशों के लिए सच है जहाँ सानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था स्वीकार नहीं की गयी है—जोर इनमें हैं ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि। कारण यह कि यदि इस तब की उसके तार्किक अंत तक ले जाया जाय तो इसका अर्थ होगा कि भारत जैसे देशों में जनता के 'प्रतिनिधि' बहुत कम हैं क्योंकि बहुत कम ही उम्मीदवार बहुमत वोट प्राप्त कर पाते हैं।

किंतु 'यायाधीन' हेगडे के तर्क की धारा स्पष्ट है। ससद जनता का प्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकती इसलिए जब कभी 'यायाधीन' आवश्यक समझें तब उस प्रतिनिधित्वपूर्ण ससद से जनता की रक्षा का काम 'यायाधीन' को करना चाहिए। इस प्रस्थापना को वह इस प्रकार पेश करते हैं

जो अधिकार स्वयं जनता के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता हो, उसको ऐसा अधिकार नहीं माना जा सकता कि उसका जनता की ओर से या जनता के हित में उपयोग किया गया है। (जोर मेरा)।

यही है इस प्रश्न का वेब्र विन्दु। क्या ससद को यह नियम लेने का अधिकार है कि अनुच्छेद ३६८ के मातहत संशोधन के अधिकार को वह जनता के हित में, उसके लाभ के लिए, इस्तेमाल कर रही है या नहीं—यह ऐसा प्रश्न है जो सारत राजनीतिक है और केवल राजनीतिक है। या यह काम किसी और अधिकारी को, 'यायाधीन' को, करना चाहिए, जिनके द्वारे में कहा जा सकता है कि वे निश्चय ही ससद से अधिक जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकते।

इसके विपरीत 'यायाधीन' राय की स्थिति स्पष्ट है, अर्थात् यह कि हमारे संविधान के अन्तर्गत प्रश्न को अगर कानूनी संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो ससद ही जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है।

२५वें संशोधन की परिधि के बारे में दोना 'यायाधीन' के दृष्टिकोण से भी उनका 'दान' प्रकट होता है।

२५वें संशोधन में जो विचारधीन प्रश्न था, वह था 'प्रतिकर' (मुआमला) दान की जगह 'राशि' शब्द का रखा जाना जिससे ससद का इरादा था कि सावजनिक कार्यों के लिए जिस व्यक्ति की सम्पत्ति राज्य ने अधिग्रहीत की है उस एक राशि के रूप में जो कुछ अदा किया जा रहा है उससे सम्बन्धित सभी

मामला को निश्चित रूप में 'मायिक' परीक्षण की सीमा से बाहर कर दिया जाय।

जिस उद्देश्य की पूर्ति का प्रयत्न किया जा रहा था, वह संविधान परिषद के सामने जवाहरलाल नेहरू द्वारा पक्ष किये गये उद्देश्य से भिन्न नहीं था, यानी यह कि 'मायालय' के क्षेत्राधिकार को बाहर रखा जाय—सिवा एम मामलों के जहाँ अदा की जाने वाली राशि (या मुआवजा—उस समय इसी अर्थ का शब्द संविधान में रखा गया था) भ्रामक हो या संविधान के विरुद्ध एक धोला हो।

आइए, हम देखें कि दो 'मायाधीन' इस प्रश्न पर क्या विचार प्रकट करते हैं।

'मायाधीन' हुगडे महसूस करते हैं कि मशोधन के बाद भी स्थिति निम्नलिखित रहती है

'मायालय' इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता कि जो कुछ अदा किया गया है या अदा किया जाना है, वह मुआवजा है या नहीं। वह इस प्रश्न पर ही विचार कर सकता है कि विवादग्रस्त "राशि" मनमाने तरीके से निश्चित की गयी या भ्रामक है या अदा की जाने वाली "राशि" निर्धारित करने के उद्देश्य में जो सिद्धांत निश्चित किये गये उनका अधिग्रहीत या अर्जित सम्पत्ति के मूल्य से तत्कालीन सम्बंध है या नहीं।

(जार मरा)।

अब अगर 'मायालय' को यह निश्चित करने का अधिकार है कि 'राशि' का सम्पत्ति के मूल्य से "तत्कालीन सम्बंध" है या नहीं तो निश्चय ही इस मामले की जांच करने में 'मायालय' का अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाना है। कारण यह कि संसद को जो बात 'तत्कालीन सम्बंध' लगती हो, वही 'मायाधीन' हुगडे को तत्कालीन सम्बंध नहीं भी लग सकती है। और इससे भी बड़ी बात यह कि "तत्कालीन सम्बंध" शब्दावली की व्याख्या करना क्या अत्यंत कठिन नहीं है? क्या इससे हम एक बार फिर विवाद के दलदल में नहीं फँस जायेंगे जिसमें कि हम अपने फैसले के सही होने के बारे में अनिश्चित बने रहेंगे, क्योंकि संसद में जाने वाली कोई ऐसी कमीटिया नहीं है जिससे इस 'तत्कालीनता' को परखा जा सके।

मायाधीन राय का प्रतिबोध भिन्न है। वह कहते हैं

राशि निश्चित करने में विधानमण्डल सचिव अधिकारों की आम प्रवृत्ति

के अनुसार वापसी करनी है। मित्रता का उद्देश्य किया जा सकता है। राशि निर्धारण करने में विधानमण्डल त्रिग मित्रता पर अमल कर सकता है, उद्यम अधिग्रहीत सम्पत्ति के मूल्य की बराबरी के मुद्राबन्ध सामाजिक धर्म का विचार शामिल किया जा सकता है। सामाजिक धर्म की विचारणा में मण्डल निर्माण मित्रता विचार अनुच्छेद ३६ (ग) और (घ) में प्रतिपादित मित्रता शामिल है। इस मित्रता का उद्देश्य सरकार द्वारा केवल की व्यवस्था करना और सामाजिक धर्म का रहना है। पदावस्था का प्रत्यक्ष विधान के चौथे अनुच्छेद का अनुच्छेद ३१ (२) में बाहर कर दिया गया है। यह तर्क है कि राशि निर्धारण करने के मामले में विधानमण्डल का पदावस्था के प्रतिमान की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। राशि की पदावस्था और एकी राशि का विचार यह किया जाता है कि यह मूल रूप में उनके तरीके के प्रत्यक्ष पर विधान निर्णय का अनुच्छेद की धारणा परीक्षा की संज्ञा है।

इस प्रकार परीक्षा वापसी का दृष्टिकोण का सार यह है कि एक और "वापसी" एक निजी व्यक्ति की सम्पत्ति के अधिग्रहण के कानून का अगर यह पाया जाय कि उक्त कानून द्वारा की जाय वाली राशि का अधिग्रहीत सम्पत्ति में "तत्कालीन सम्पत्ति" नहीं है, अवश्य धारित करना कि अधिग्रहण "वापसी" के पाग मुद्राबन्ध रखने के। इस विचार वापसी का सार यह है कि तो पदावस्था की परीक्षा की जा सकती है और राशि निर्धारण करने में विधानमण्डल द्वारा निर्धारित प्रतिमान की जाय की जा सकती है। उनके मतानुसार "वापसी" द्वारा "राशि" के आधार की जाय का प्रत्यक्ष विधान के चौथे अनुच्छेद का अनुच्छेद द्वारा और उसमें भी अधिग्रहण स्पष्ट रूप में २५वें अनुच्छेद द्वारा धारित विचार क्षेत्र में बाहर कर दिया गया है तथा यह सिद्ध विधानमण्डल के विचारक्षेत्र का प्रत्यक्ष है।

अतः, आइए हम अनुच्छेद ३१ में परीक्षा "वापसी" का दृष्टिकोण देखें। यहाँ पहले इस बात पर ध्यान आवश्यक है कि अनुच्छेद का सार यह है कि अनुच्छेद ३६ (ग) और ३६ (घ) में प्रतिपादित विधान सिद्धान्त की यह मूल अधिवार में ऊपर रखना है। इससे व्यक्ति के अधिग्रहण, समान की आवश्यकताओं के अधीन कर दिये गये हैं।

१. इस सीमित प्रश्न पर विधानमण्डल अनुच्छेद ३१ में चौथे अनुच्छेद के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही थी या नहीं मतदान के अंक द्वारा देने वाले ६ और सभी में इस संशोधन के समर्थन में ३५३ संख्याओं ने मत दिये और विरोध में केवल २० ने राय मता में १६६ संशोधन में मत दिये और विरोध में केवल २० ने

स्पष्ट ही, इस प्रकृति का निणय राजनीतिक है। ऐसे निणय का समर्थन या विरोध करने में जिस बात को ध्यान में रखना चाहिए वह यह कि ऐसा निणय सिर्फ राजनीतिक ही हो सकता है। इन निदेशक सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए जिन सम्पत्तिधारियों की सम्पत्ति अधिग्रहण की जान वाली होती है, वे निश्चय ही यह महसूस कर सकते हैं कि अनुच्छेद ३१ (ग) बहुत सख्त और दानवी है क्योंकि वह उन्हें अनुच्छेद १६ (१) (छ) और अनुच्छेद (३१) (२) के संरक्षण से वंचित करता है। किंतु यह भी मतामत का प्रश्न है—आम अवाम जिनके हितों में ऐसी सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जायगा निश्चय ही अनुच्छेद ३१ ग द्वारा इस अधिग्रहण को दिये गये संरक्षण को सराहेंगे।

इस प्रकार सम्पत्ति के स्वामियों के प्रवक्ता अनुच्छेद ३१ ग के विरुद्ध शोर-गुल मचायेंगे जबकि वे लोग जो निदेशक सिद्धांतों के माग पर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं उसका मोत्साह अभिनंदन करेंगे। किंतु जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ, वह यह है कि दृष्टिकोण कुछ भी हा, मूलतः वह राजनीतिक उद्देश्या पर आधारित एक राजनीतिक दृष्टिकोण होगा।

मगर 'यायाधीश' हगडे को इस अनुच्छेद की निंदा के लिए काफी सख्त शब्द नहीं मिलते। वह कहते हैं

उसके (अनुच्छेद ३१ ग) द्वारा दिये गये अधिकार मनमाने अधिकार हैं। उसको स्वायत्त उद्देश्या के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको भाषण की स्वतंत्रता शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता भारत भर में मुक्त रूप में घूमने की स्वतंत्रता भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता सम्पत्ति अधिग्रहण करने उसका स्वामी बनने और उसको बेचने की स्वतंत्रता तथा कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या सौदा करने की स्वतंत्रता का गला घोटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस व्यवस्था में दिये गये अधिकार निरपेक्ष अधिकार हैं। विधानमण्डल का एक छोटा-सा बहुमत भी उस अधिकार को जनतंत्र को सीमित करने या उसको नष्ट करने तक के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वह अधिकार इस देश की अखण्डता का निराल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वह अनुच्छेद हमारे संविधान में चिनकूल बसेल है।

'यायाधीश' राय इस मामले को भिन्न तरीके में देखते हैं। वह कहते हैं

जिन कानूनों को अनुच्छेद ३१ ग के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान की गयी है वे अनुच्छेद ३६ (ग) और (ग) के निदेशक सिद्धान्तों का उपलब्ध करन के

बानूत हैं। इस आधार पर कि बार्ड बानूत एमो नीति पर अमन नही करता "सायानथ मे उमगा चुगौती" में जात म भुक्त रगत की घायला करने का अगती बाग्य यह है कि बानूत बानूत की नीति और विवेक का विवेक विधानमण्डल पर छाया जात। एम बन्मा क मूल्यानन और उन पर पगत का हा उम घायला हाग "यायिक पुनरीक्षण म बाहर रगत का प्रपरा रिया गया है।

और जा

अनुच्छेद ३१ म का उद्देश्य है मध्यातिर आग हाग मग और राग का बानूत बानूत क अधिकार दात।

इस प्रकार दाता "यायाधीन" क अभिगम म भूत अंतर है। "यायाधीन" एम की आर स अनुच्छेद ३१ म की निदा हर्द "यायाधीन राय की आर न त ता इस अनुच्छेद का ममपत रिया गया और न निग बन्वि यह मायना मिनी की यह मायना "बानूत बानूत की नीति और विवेक" के क्षेत्र म आता है।

और यह यह टीका करना मगत हागा कि किसी "यायाधीन" क लिए इस निष्पक्ष पर पठ्यता कि अनुच्छेद ३१ म "पूणतया हमार सविधान स बनल है" एक राजनीतिक मत्र मात्र अभिव्यक्त करता है—क्या कि जा कारण से वह इस निष्पक्ष पर पगे, क राजनीतिक प्रवृत्ति के हैं।

ऊपर जिन पसला के उद्घरण दिय गय हैं उनम इस प्रकार "यायाधीन" का "गन ममभने म सहायता मिलती है। और हम यह बात स्पष्ट रूप म समझ लेनी चाहिए कि यह दान विही गहरी गस्तिया के समभाव-बुभाव या प्रभाव स नही पैदा हाता और न ही किसी बुरे इराद के कारण। हमार समय की तूफानी घटनाओं का "यायाधीन" जिस तरीके स देखात है यह दान उसम ही पैदा हाता है। एजवेल्ट के दिना म जमरीना क उच्चतम "यायालय" के चार "यायाधीन" महसूस कर रहे थे कि "राष्ट्रपति देग का मिना की गिना म ले जा रह हैं, सविधान की आत्मा की भ्रष्ट कर रह हैं आदि उसके विपरीत तीन अय "यायाधीन", एजवेल्ट के सुधारा को बानून निर्मात्री नीति और विवेक के रूप म दखत थे तथा "यायिक पुनरीक्षण की परिधि के बाहर समभन थे। यही था "यायाधीन" के दान म अंतर।

जाज भारत म स्थिति उससे भिन्न नही है। और "यायाधीन" के पसला (अब्राहम लिंकन के शब्दों म उनकी रायों) को निष्पक्ष रूप से पने पर

निश्चय ही उनके युनियादी दंगना, जीवा सम्प्रधी उनके दृष्टिकोणों का वैयक्तिक प्रकट हो जाता है।

“यायाधीश हमडे ने, अपने इस्तीफे के लागू हो जाने के तुरन्त बाद, १ मई १९७३ का एक सवाददाता सम्मेलन में जो बयान दिया था, वह उनके दशन, उनके जीवन सम्प्रधी दृष्टिकोण, को और अधिक उजागर करता है। उसमें उन्होंने कहा

जनतंत्र केवल एक सशक्त विरोध पक्ष, जागृत जनमत, आलोचनाशील समाचारपत्र व्यवस्था और स्वतंत्र “यायपालिका” से ही जीवित रह सकता है। लेकिन आज विभिन्न कारणों से कोई सशक्त विरोध पक्ष नहीं है और जनमत को भी जागृत नहीं करा जा सकता क्योंकि पचास प्रतिशत से अधिक आवादी निरक्षर है। समाचारपत्र भी पाबंदियाँ में मुक्त नहीं है।

और तब उन्होंने टीका की कि “आप में से अनेक लोग केवल सरकार की सराहना करने का स्वतंत्र हैं।”

अतः यह कहते हुए कि एक मात्र बची हुई रक्षक शक्ति है एक स्वतंत्र “यायपालिका”, जिसका ‘सफाया’ किया जा रहा है” उन्होंने आह्वान किया कि “जनतंत्र की अभी भी रक्षा की जा सकती है बशर्ते कि जनता जाग, उठ पड़ेगी और अपनी दक्षिण पाँव उभार कर चलने का प्रयत्न करे।”

इसमें क्या प्रकट होता है? निम्नतः, एक सशक्त विरोध पक्ष, एक निम्न और स्वतंत्र समाचारपत्र व्यवस्था और जागृत जनमत महत्वपूर्ण है ताकि सरकार का इतना विरोध और ईमानदारी से इतनी आलोचना हो सके कि जिसमें हमारे देश के सामने उपस्थित महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्याओं पर उचित बाद विवाद आश्वस्त हो जाय, और सरकार तथा संसद को ऐसे रास्ते के बारे में जिस पर हमारे देश को चलना चाहिए सही फैसले करने में सहायता मिले।

लेकिन लगता यह है कि “यायाधीश हमडे के लिए भारत में सिर्फ “यायालय” महत्वपूर्ण है, सिर्फ “यायालय” ही “जनतंत्र के अंतिम रक्षक” हैं।

उनके मतानुसार समाचारपत्र व्यवस्था किसी मसरफ की नहीं है क्योंकि उसका सिर्फ सरकार की सहायता करने की इजाजत है—यह तथ्या को देखने से इनकार करने की अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में समाचारपत्र अपनी बात कहने के लिए इतने स्वतंत्र नहीं हैं जितने कि भारत में। वह यह भी कहते हैं कि हमारी जनता में पचास प्रतिशत लोग

विश्व है। दुनिया में क्या। विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं हैं। कि समझ
 गये कि उन्हे अपनी ही बात है। जगत् पर क्या फिर भारतीय विश्व के
 विश्व में उन्ही गणतन्त्रही प्रकट होते हैं क्योंकि जिस विचार ने भी हमारे
 देश के गणतन्त्र जीवन का भाव दिया है या हमारी जाति के बीच प्रभा
 दिया है जाति है कि हमारी जाति स्थापन रूप में जाति है और मनी भाति
 जाती है कि उन्हा दिया गया है। हम उन्हे स्थिति की परिचयता और
 गणतन्त्र का भाव बन जा उन्हा विचार चुना। म प्रवृत्ति की जब अत्यन्त
 उप विराधी गणतन्त्र जगत् और 'द्वारा' जनता के सभी नाना की
 का भविष्यविज्ञान के बावजूद कि द्वितीय गांधी का चुनाव म विचार का
 सामना करना पड़ेगा जाति उत्थापन म आग बनी और उन्ही भारतीय चुनाव
 के विचार म गणतन्त्र अतिरिक्त भारी विचार दी।

और क्या जगत् में 'वायवाधीन' रूप बहन है कि कोई गणतन्त्र विचार का
 नहीं है। लेकिन हम मानते हैं कि जो लोग गणतन्त्र में बैठते हैं वे उन् समय
 विचार का की गणतन्त्र प्रत्यक्ष क्षेत्र में देख सकते हैं जब वह सरकार का
 मुताबक करी का गण होता है। मगर सामान्य दृष्टि ही नहीं है कि श्री
 एम. भारती और हमारी जाति का उन् रूप म जगत् म दूसरों बन हैं जैसी
 कि यह है हमारे देश के गणतन्त्र जीवन का उन् रूप म दृष्टि में दूसरों बन
 हैं जिस रूप म वह गणतन्त्र और दृष्टि का की गणतन्त्र बन स
 हैं कि हमारे देश म गणतन्त्र का की भूमिका विचार गणतन्त्र है।

दृष्टि भी अधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि अपने दृष्टि में कि यहा
 कोई स्वतन्त्र गणतन्त्र नहीं है यदि जागृत जागृत नहीं है और यदि
 गणतन्त्र विरोध का नहीं है वह हम तीजे पर पड़ते हैं कि "जनतन्त्र की
 अंतिम रचना" वायवाधिन है।

यह निश्चय कहा जा सकता है। हम कोई भी 'यति' इसी स्थिति पर
 पहुँचेगा कि वायवाधिन पर गणतन्त्र गणतन्त्र बने कि वायवाधीन ही हैं, उन्
 ही वायवाधिन पर बराबर तजर रगनी और उन्का पदवर्धन करता है तथा
 उन्ही उसवे एम एम का विरोध ना स जाचना होगा।

यहा वायवाधीन गणतन्त्र के दृष्टि प्रकट नहीं होता कि उन्के
 लिए एक और 'वायवाधिन' और दूसरी और सरकार तथा गणतन्त्र के बीच
 मुताबक की हानि जारी रगता एम उचित स्थिति है ?

इस सभ्य यह समझने का महत्व रेखांकित होता है कि एम 'वायवाधीन'
 किस प्रकार जीवन को देवता है एम 'वायवाधीन' और दूसरे के दृष्टिकोण म
 अन्तर क्या है और वादों के दृष्टि में, वायवाधीन के "दृष्टि", उन्के
 "दृष्टिकोण", की धारा म रचना तथा एम जीवित आवश्यकता है।

७ पदोन्नति और वरीयता

वरीयता के प्रश्न को लेकर तक वित्तक काफी परिमाण में बढ़ा है, यानी यह कि 'यायपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए मुख्य 'यायाधीश के पद के लिए पदोन्नति में वरीयता (सीनियोरिटी) के नियम का पालन परमावश्यक है। जय देशा का अनुभव छोड़ भी दिया जाय (जिस पर अध्याय ४ में विस्तार में विचार किया गया है) तो भारत में भी उच्च 'यायालयों के मुख्य 'यायाधिपति की नियुक्ति या उच्च 'यायालयों से उच्चतम 'यायालय में उन्नत नियुक्ति के मामले में वरीयता के सिद्धांत की अवहेलना भी बिल्कुल कम नहीं हुई है। मैं यहां अनेक उदाहरण दे रहा हूँ और यह सूची किसी भी प्रकार पूरी नहीं है

(१) दम्बरू उच्च 'यायालय के 'यायाधीश जे आर मुद्गोलकर को उच्चतम 'यायालय में ३१० १९६० में नियुक्त किया गया। उनकी उस समय उच्च 'यायालयों के सभी मुख्य 'यायाधिपतियों के मुकाबले तरजीह देकर चुना गया और विभिन्न उच्च 'यायालयों के स्थायी 'यायाधीशों में उनकी स्थिति सातवें नम्बर पर थी।

(२) कलकत्ता उच्च 'यायालय के 'यायाधीश आर एम बच्चवत की नियुक्ति उच्चतम 'यायालय में ७६ १९६४ को की गयी। उनको भी उस समय के सभी उच्च 'यायालयों के मुख्य 'यायाधिपतियों के मुकाबले

तरजीह देकर उच्चतम 'यायालय' में नियुक्त किया गया और विभिन्न 'यायालया' के स्थायी 'यायाधीश' में उनका स्थान दूसरे नम्बर पर था।

(३) कलकत्ता उच्च 'यायालय' के 'यायाधीश' जी के मित्तर का उच्चतम 'यायालय' में २६ न १९६६ को नियुक्त किया गया। उस समय कलकत्ता उच्च 'यायालय' में उनसे प्रवर (सीनियर) तीन (मुख्य 'यायाधिपति' समेत) 'यायाधीश' थे और विभिन्न उच्च 'यायालया' के स्थायी 'यायाधीश'ों में उनका स्थान आठवा था।

(४) केरल उच्च 'यायालय' के 'यायाधीश' सी ए वैदर्यालिंगम को उच्चतम 'यायालय' में १ न १ न १९६६ का नियुक्त किया गया। उस समय स्वयं केरल उच्च 'यायालय' में दो अन्य 'यायाधीश' (मुख्य 'यायाधिपति' समेत) को उनसे वरीयता प्राप्त थी और विभिन्न उच्च 'यायालया' के स्थायी 'यायाधीश'ों में उनका स्थान तेइसवा था।

(५) पंजाब और हरियाणा उच्च 'यायालय' के 'यायाधीश' ए एन शत्रुघ्न को उच्चतम 'यायालय' में १२ न १९६६ को नियुक्त किया गया। उस समय पंजाब और हरियाणा उच्च 'यायालय' में ही दो अन्य 'यायाधीश'ों को (जिनमें मुख्य 'यायाधिपति' भी थे) वरीयता प्राप्त थी और विभिन्न उच्च 'यायालया' के स्थायी 'यायाधीश'ों में उनका स्थान उतालीसवा था।

(६) बलकत्ता उच्च 'यायालय' के 'यायाधीश' ए एन राय उच्चतम 'यायालय' में १ न १९६६ का नियुक्त किया गया। उस समय बलकत्ता उच्च 'यायालय' में तीन अन्य 'यायाधीश' (मुख्य 'यायाधिपति' समेत) का उनसे वरीयता प्राप्त थी और विभिन्न उच्च 'यायालया' के 'यायाधीश'ों में उनका स्थान तीसवा था।

(७) बम्बई उच्च 'यायालय' के डी जी पालेकर को उच्चतम 'यायालय' में १६ न १९७१ में नियुक्त किया गया। नियुक्ति के समय स्वयं बम्बई उच्च 'यायालय' में पांच अन्य 'यायाधीश' (मुख्य 'यायाधिपति' समेत) उनसे प्रवर थे और विभिन्न उच्च 'यायालया' के स्थायी 'यायाधीश'ों में उनका स्थान चौतीसवा था।

(८) केरल उच्च 'यायालय' के के के मैथ्यू उच्चतम 'यायालय' में ४ न १९७१ को नियुक्त किया गया। नियुक्ति के समय स्वयं केरल उच्च 'यायालय' में तीन अन्य 'यायाधीश' (मुख्य 'यायाधिपति' समेत) का उनसे वरीयता प्राप्त थी और विभिन्न उच्च 'यायालया' के स्थायी 'यायाधीश'ों में उनका स्थान गन्तरवा था।

(९) उत्तराखण्ड उच्च 'यायालय' के एन एन द्विवेदी उच्चतम 'यायालय' में १ न १९७२ का नियुक्त किया गया। नियुक्ति के समय स्वयं उत्तराखण्ड

उच्च न्यायालय में दो अथवा यायाधीश (मुख्य यायाधिपति समेत) उनसे प्रवर थे और विभिन्न उच्च न्यायालयों के स्थायी यायाधीशों में उनका स्थान दसवा था ।

(१०) कलकत्ता उच्च न्यायालय के ए के मुखर्जी उच्चतम न्यायालय में १४ न १९७२ को नियुक्त किये गये । नियुक्ति के समय स्वयं कलकत्ता उच्च न्यायालय में तीन अथवा यायाधीशों (मुख्य यायाधिपति समेत) का उनसे बरीयता प्राप्त थी और विभिन्न उच्च न्यायालयों के स्थायी यायाधीशों में उनका स्थान दसवीसवा था ।

(११) बम्बई उच्च न्यायालय के वार्ड बी चन्द्रचूड को उच्चतम न्यायालय में २३ न १९७२ को नियुक्त किया गया । नियुक्ति के समय स्वयं बम्बई उच्च न्यायालय में दो अथवा यायाधीशों (मुख्य यायाधिपति समेत) को उनसे बरीयता प्राप्त थी और विभिन्न उच्च न्यायालयों के स्थायी यायाधीशों में उनका स्थान उन्नीसवा था ।

(१२) मद्रास उच्च न्यायालय के ए अनगिरिस्वामी उच्चतम न्यायालय में १७ १० १९७२ को नियुक्त किये गये । नियुक्ति के समय स्वयं मद्रास उच्च न्यायालय में पांच अथवा यायाधीशों (मुख्य यायाधिपति समेत) को उनसे बरीयता प्राप्त थी और विभिन्न उच्च न्यायालयों के स्थायी यायाधीशों में उनका स्थान बहत्तरवा था ।

(१३) के एस हेगडे को विभिन्न उच्च न्यायालयों के २८ अथवा स्थायी यायाधीशों पर तरजीह देकर दिल्ली उच्च न्यायालय में अक्टूबर १९६६ में मुख्य यायाधिपति नियुक्त किया गया । फिर उन्हें जुलाई १९६७ में उच्च न्यायालयों के तमाम मुख्य यायाधिपतियों के मुकाबले, जो सब मुख्य यायाधिपति के रूप में उनसे प्रवर थे, तरजीह देकर सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया ।

(१४) १९४७ में एम सी छागला को उनसे प्रवर के सी सेन का अधिष्ठापन कर बम्बई का मुख्य यायाधिपति नियुक्त किया गया ।

(१५) पी बी मुखर्जी का, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के सबसे प्रवर सदस्य थे, मुख्य यायाधिपति की नियुक्ति के मामले में दो बार अधिष्ठापन किया गया । जून १९६१ में एस सी लाहिड़ी के अवकाश प्राप्त करने के फलस्वरूप कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्य यायाधिपति का पद खाली हुआ । हालांकि पी बी मुखर्जी उस समय सबसे प्रवर यायाधीश थे, फिर भी किन्हीं कारणों से उन्हें छोड़ दिया गया और एच के बाम को, जो उनसे अवतर (जूनियर) थे, मुख्य यायाधिपति नियुक्त किया गया । पी बी

मुखर्जी को माच १९६६ में फिर छोड़ दिया गया और डी एन सिन्हा को, जो उनसे ऊपर थे मुख्य 'यायाधिपति' नियुक्त कर दिया गया।

(१६) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अक्टूबर १९५९ में मुख्य 'यायाधिपति' की नियुक्ति के लिए प्रचुरतम 'यायाधीश' टी पी नायक का पी वी दीक्षित द्वारा अधिक्रमण किया गया। उसी उच्च न्यायालय में माच १९६६ में पुनः टी पी नायक का अधिक्रमण किया गया जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशम्भर दयाल को मध्य प्रदेश का मुख्य 'यायाधिपति' नियुक्त किया गया। स्थायी 'यायाधीश' के रूप में विशम्भर दयाल टी पी नायक से ऊपर थे।

इन सभी अनगिनत उदाहरणों से प्रकट होता है कि 'प्रत्येक' चरण में, वह चाहे किसी उच्च न्यायालय के मुख्य 'यायाधिपति' की नियुक्ति का प्रश्न था या उच्चतम न्यायालय के 'यायाधीश' की नियुक्ति का प्रश्न सचयन हमें 'यायाधीश' के गुणों के आकलन के आधार पर और न्यायालय में उसकी उपयोगिता को ध्यान में रख कर किया गया। वरीयता को एक नियम के रूप में, स्पष्ट-तया, अधिक महत्व नहीं दिया गया।

इस प्रकार, आम तौर पर उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति वरीयता पर आधारित नहीं रही। तो भी यह दलील कभी नहीं दी गयी कि इस 'यायपालिका' की स्वतंत्रता को क्षति पहुँची है। बार्द गिराफत नहीं की गयी कि उच्चतम न्यायालय में अपनी पदोन्नति की जाँच कर उच्च न्यायालयों के 'यायाधीश' ने 'अनुमति' या 'सुगम' कर वापसपान को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था। इसलिए यह बिनाम करना बड़बुद है कि जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य 'यायाधिपति' के पद पर नियुक्ति के मामले में वरीयता के नियम का पालन नहीं किया जाता है, तभी 'यायपान' की स्वतंत्रता पर पूरी तरह मुठभरान होता है।

अमन में लगा लगता है कि यह भय हमारा देश की सर्वोच्च अदालत, उच्चतम न्यायालय, के 'यायाधीश' के बौद्धिक और नैतिक चरित्र की गति का दुर्भाग्यपूर्ण कम मूल्यांकन पर आधारित है। आगिर हम उच्चतम न्यायालय के मुख्य 'यायाधिपति' के पद पर उच्चतम न्यायालय के 'यायाधीश' में से हा नियुक्ति पर विचार कर रहे हैं यानी अपने देश के 'यायिक' साधन के उच्चतम स्तर के लिए हमें लगाना में सचयन पर विचार कर रहे हैं जो अपने उच्च गुणों के लिए सम्मान्य हैं। निश्चय ही काम और अधिकार के उच्च स्तर पर उच्च न्यायालय का प्रभावित होगा। क्या यह कहना की जा सकती है कि उच्चतम

पद पर नियुक्ति की आशा में यायाधीश कानून को भ्रष्ट करने और अपने विवेक के विरुद्ध फैसले देने के लिए तैयार होंगे ?

हमारे देश के लिए यह दुखद दिन होगा जब हम यह भय होने लगेगा कि उच्चतर पद की आकांक्षा, अर्थात् यायाधीश के पद से उच्चतम यायालय के मुख्य यायाधिपति पद पर पदोन्नति की सम्भावना, उच्चतम यायालय में उनके यायिक काम के संचालन के लिए यायाधीशों को प्रभावित करेगी और विशेषकर उन्हें सरकार के पक्ष में फैसले देने के लिए प्रभावित करेगी। राज्य सभा में अपने भाषण में सी के दफ्तरी का यह तर्क कि ए एन राय को मुख्य यायाधिपति नियुक्त करने के सरकार के निर्णय से, और इस प्रकार वरीयता की प्रथा को तिलाजलि दिये जाने से, न्यायाधीशों द्वारा "झूठे चाटा जाना" शुरू हो जायगा—हमारे यायाधीशों की योग्यता को कतई श्रेय नहीं दे ।।

८. निष्कर्ष

उन सभी चारों देशों में जिनके अनुभव की इस मामले में कुछ विस्तार से परीक्षा की गयी है, राजनीतिक पद (केवल राजनीतिक दृष्टिकोण ही नहीं) को नियुक्ति के लिए अयोग्यता समझना तो दूर रहा, एक योग्यता माना जाता है—उच्च यायिक नियुक्ति के लिए सम्भवतः निर्णायक योग्यता। हमने अपने देश में इस अभिगम को स्वीकार नहीं किया है और उसको स्वीकार करना शायद हमारी राष्ट्रीय परम्परा के उपयुक्त नहीं होगा।^१

किंतु निश्चय ही, जीवन का ज्ञान, ऐसे विचारों और इरादों का ज्ञान जो करोड़ों के दिमागों को झकझोर रहे हैं, समय की गति के साथ चलने की क्षमता जो लोग बहुत ही जल्दबाजी के लिए कसमकस कर रहे हैं उनकी आकांक्षाओं का सहानुभूति के साथ समझने योग्य दृष्टिकोण—क्या कोई इंतजार कर सकता है कि इस उच्च पद के प्रत्येक उम्मीदवार में ये सारे गुण भारी परिमाण में होने चाहिए ?

- १ किंतु यायाधीश हेगरे ने हाल में बताया था कि मीडे राजनीतिक जीवन से 'यायाधीश' पद पर नियुक्तियाँ भारत में प्रविद्ध नहीं हैं उनके स्वयं के उदाहरण के अतिरिक्त यायाधीश मल्लहारे, टेन्चर तथा न्यायाधीश शंकर प्रसाद मिश्र जो अब कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, के भी उदाहरण हैं मगर आम तौर पर वे अपवाद हैं नियम नहीं

प्रश्न पूछा जा सकता है नियुक्ति के लिए सम्भावित व्यक्तित्व के "दृष्टिकोण", उसके (वाहोंजा के शब्दों में) "दशन" को परगने के लिए उसको कैसे देखना चाहिए। शायद सर्वोत्तम उत्तर यह है जो जीवन की जननाश्रय प्रणाली के महान अप्रदूत अब्राहम लिंकन^१ ने दिया था। उन्होंने इस प्रश्न का निम्नलिखित रीति से उत्तर दिया था

हम किसी व्यक्ति से यह नहीं पूछ सकते कि वह क्या करेगा, और अगर वह इसका जवाब दे भी बैठे तो हमें उसके लिए उससे नफरत करनी चाहिए। इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को लेना चाहिए जिसके विचार सुविदित हों।

शिकायत की गयी है कि "यायाधीन" का "अधिनमण" किया गया, कि इस नीति से "यायपालिका की स्वतंत्रता नष्ट हो जायगी, आदि। किंतु क्या संविधान के अंतर्गत सरकार को यह छूट नहीं मिली हुई है कि एक "यायाधीन" और दूसरे "यायाधीन" के बीच वह जागरूकता से चयन करे, ईमानदारी से और "यायपूर्वक" इस नतीज पर पहुंचे कि उसकी राय में एक खास व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक उपयुक्त, अधिक समतावान और अधिक कारगर मुख्य "यायाधिपति" हो सकता है? इससे न चुने गये व्यक्ति पर कोई आपेप नहीं आता, क्योंकि एक सरकार नियुक्ति के लिए सम्भावित व्यक्तियों के "निचारों" का (बकील अब्राहम लिंकन) अपनी नजर से, अपन चक्षु से, देखती है और कोई दूसरी सरकार उसी मामले को भिन्न तरीके से देख सकती है। लेकिन लाजिमी तौर पर सरकार के ऊपर यह कतव्य आया है कि वह मामले की सभी कोणा से परीक्षा करे और सबसे अधिक उसको ध्यान देना चाहिए "यायिक सत्यनिष्ठा तथा कानूनी ज्ञान के साथ उसके "दृष्टिकोण", उसके "दशन" पर यानी इस बात पर कि उसको परिवर्तित भारतीय दृश्य का और जिस दिशा में देश जाना चाहना है उस दिशा का बोध है या नहीं।

सरकार को सचयन के इसी कायक्षेत्र का प्रत्येक ऐसे मामले में सामना करना होता है जहां उसको नियुक्ति का अधिकार है—मंत्रिमण्डल का सचिव, आर्मी स्टाफ का प्रधान, सावजनिक सेवा आयोग का अध्यक्ष—क्या वरीयता से ही सत्ता यह निर्धारित किया जाता है कि नियुक्ति योग्य कौन व्यक्ति है? या

१ अब्राहम लिंकन ने यह उत्तर उस समय दिया था जब तत्कालीन वित्त सचिव चैत्र को अमरीका के उत्तम यायिक पद उच्चतम यायालय के मुख्य "यायाधिपति" के पद पर नियुक्त किये जाने पर उन से प्रश्न पूछा गया था।

निर्णय करने से पहले क्या सभी सदन पक्षा पर ईमानदारी और मावधानी से विचार किया जाता है और अग्रेसर ही वरीयता को तिलाजति दी जाती है, अधिग्रहण होते हैं ?

यही पृष्ठभूमि है जिसमें "अधिग्रहण" हुए हैं और हो सकते हैं, ऐसा हर अंग्रेजी भाषी दंग में हुआ है और कोई कारण नहीं कि भारत का अपवाद बनाया जाए।

इस सबसे सम्भवतः उस अधिग्रहण और उस इरादा की पर्याप्त तथा ईमानदारी के साथ सफाई हो जाती है कि जिनसे सरकार उच्चतम "यायाधिश" के मुख्य "यायाधिश" के उच्च पद के लिए "यायाधीश" राय को चुनने में प्रेरित हुई। और साधारणतः मैं किसी पदार्थ "यायाधीश" के गुणा-अवगुणों पर बहुत से पहना उचित नहीं समझता, रास कर एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो भारत का मुख्य "यायाधिश" है। किंतु चूंकि उन पर अनुचित आक्रमण हुए हैं मैं उनको साह्य और सत्यनिष्ठा का हवाला दिये बिना नहीं रह सकता।

मुख्य यायाधिश राय ने १९३६ में कलकत्ता उच्च "यायालय" में बरिस्टर की हैसियत में कानूनी जीवन शुरू किया था। वह १९५७ में कलकत्ता उच्च "यायालय" में यायाधीश और १९६६ में उच्चतम "यायालय" में "यायाधीश" नियुक्त हुए। और "यायाधीश" के रूप में उनका कार्य-जीवन न सिर्फ लम्बा, बल्कि विशिष्टतापूर्ण रहा है।

यह आरोप भ्रष्टा है कि उन्हें मुख्य यायाधिश इसलिए नियुक्त किया गया कि उन्होंने उन तीन बड़े मुकदमों में जिनका उन्होंने फैसला किया—पहला बक राष्ट्रीयकरण का, दूसरा, प्रिवी पंच का और तीसरा, हाल का बड़ा सबवानिफ मामला—उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला देकर उसको अनुग्रहीत किया।

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि जहां तक बैंक राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पंचों के मुकदमों का सम्बन्ध है "यायाधीश" राय के फैसले में मूलतः उच्चतम "यायालय" द्वारा घोषित पिछली कानूनी स्थितियों की पुष्टि ही थी—उन स्थितियों की पुष्टि जिन्हें दुर्भाग्य से बहुमत ने मन्सूख कर दिया था और अप्राज्ञ बताया था। इसलिए इन मामलों में "यायाधीश" राय के विचारों का ऐसा मानना कि वे सरकार की इच्छाओं को ध्यान में रख कर व्यक्त किये गये थे, जानबूझ कर और बेईमानी के साथ उनको बदनाम करना है।

और हाल के सबैधानिक मुकदमों में "यायाधीश" राय मोलवनाथ मुखर्जी को मन्सूख करने में नौ अन्य "यायाधीशों" के साथ थे और २४वें तथा २५वें सलाहकों की रचना का अनुमोदन करने में पांच अन्य "यायाधीशों" के साथ थे। यह भी नोट करना अच्छा होगा कि इन मशायदों को सदन के दोनों सदनों में लगभग सबसम्मत मसौदा प्राप्त हुआ था और इस प्रकार उनमें लिए यह

सद्व्येष्ट रूप से दावा किया जा सकता है कि ये जनता की इच्छा अभिव्यक्त करते हैं। इस मामले में यह बात किसी प्रकार असंगत नहीं है।

इसके अतिरिक्त, अभी हाल में तीन महत्वपूर्ण मामला में 'यायाधीन' राय एमे फैसलो में शामिल थे जो सीधे सरकार के खिलाफ थे। 'यूज प्रिंट (अम्बारी कागज)' पर नियंत्रण के मामले में 'यायाधीन' राय 'यायालय' के बहुमत के साथ थे जिसने उम आदेश को रद्द किया। बहुत हाल में आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कानून की धारा १७-ब की कथता के मामले में 'यायाधीन' राय उस बेंच के सदस्य थे जिसने उसको अवैध घोषित किया। सम्पत्ति-कर के मामले में वह उस बहुमत के विरुद्ध थे जिसने कानून को वैध ठहराया।

तब इस मामले का सार क्या है?

पहली बात यह कि जनतांत्रिक व्यवस्था के उचित रूप से काम करने के लिए यह कोई अनिवार्य पूर्व शर्त नहीं है कि मुख्य 'यायाधिपति' का वरीयता के आधार पर नियुक्त किया जाय, बल्कि इसके विपरीत ऐसी प्रथा में हानिकारक परिणाम ही हो सकते हैं।

दूसरी बात यह कि जनतांत्रिक व्यवस्था के उचित रूप से काम करने के लिए यह कोई अनिवार्य पूर्व शर्त नहीं है कि कोई 'यायाधीन' अपनी नियुक्ति से पहले तक राजनीतिक विचारों या विश्वासों में अवरोध हो—अगर ऐसा व्यक्ति सोज निकालना सम्भव हो तब भी।

तीसरी बात यह कि 'सावजनिक' मामला का कुछ ज्ञान या उन व्यापकतर विचारों का ज्ञान जो कराड़ों के दिनों दिमाग को आंदोलित करते हैं दश के उच्चतम 'यायालय' में नियुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण योग्यता है।

चौथी बात यह कि जिस व्यक्ति को उस समय की सरकार देश के सर्वोच्च 'यायिक' पद पर बैठने के लिए अपनी नज़र में सबसे अधिक योग्य समझती है उसको नियुक्त करना और उसके दायन तथा जीवित सम्बन्धी दृष्टिकोण पर विचार कर उसका भी ध्यान रखना सबका सरकार के अपने विवेक का अंग है।

पाचवीं बात यह कि किसी 'यायालय' के काम करने की अत्यन्त महत्वपूर्ण

१ मतदान इस प्रकार था

	लोर	सभा	राय	सभा
	है	नहीं	है	नहीं
२४वाँ सरोधन	३८८	२३	१७७	८
२५वाँ सरोधन	३५३	२०	१६६	२०
२६वाँ सरोधन	३८१	६	१६७	७
२६वाँ सरोधन	३११	शून्य	१७०	१४

विशेषता हानी चाहिए कानून के प्रमुख और जीवन्त प्रश्नों के मामले में सुनिश्चितता और स्थायित्व।

जब मौजूदा मुख्य यायाधिपति की नियुक्ति के विषय में वाद विवाद का तूफान थम जायगा तब मुझे काट मार नही हूँ कि एक स्पष्टतः गलत प्रथा और अमन से हटने का यह पहला उदाहरण भाग्यीय यायालया के इतिहास में एक माय चिह्न माना जायगा। फिर भी विवाह की प्रकृति से ही सम्भवतः इस प्रश्न से सम्बन्धित मामला की जानकारी फैामी कारण कि यह बात अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में इस समय जा तक बितक और मनों भाव उभर रह हैं उनका बहुत कुछ आधार यह है कि सम्बन्धित मुख्य मसल का जितनी गहराई में समझा जाना चाहिए, उसका निरान्त अभाव है (शायद उसका अध्ययन तब करन में दनसार किया जा रहा है)।

६. उपसंहार

यह पुस्तक जिस समय प्रेस में गयी, उस समय के बाद से ए एन राय को मुख्य 'यायाधिपति' नियुक्त किये जाने के विरुद्ध निहित स्वार्थों की ओर सचोतरफा संगठित अभियान बढ़ा दिया गया है। इस अभियान के अगुआ उनसे सत्रसे अप्रगण्य प्रवक्ता एन ए पानकीवाला हैं। यह कोई आपस्मिक धान नहीं कि वह 'राष्ट्रीयकरण' के मामले में वह वह मालिकों के, गिरी पत्तों के मामले में रजवाड़ा के, और सत्र में ताजा सविधान गन्तोत्रन के मामले में जमींदारों के वकील थे।

इस अभियान का निर्माण करने में स्वभावतः इन निहित स्वार्थों ने सामान्यतः सरकार द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण को, और विशेषकर मेरे दृष्टिकोण को, तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भरपूर प्रयत्न किया है।

पानकीवाला ने दलील दी है कि "सविधान चूँकि एक प्राणवत् जीवी है अतः उसका अपना दशन है। 'यायाधीश' सविधान और कानून की रक्षा करने की दायर्य लेता है। अगर 'नासक' पार्टी का दशन सविधान के दशन के विरुद्ध है तो उसे कानून से दशन की रक्षा करनी चाहिए?" (इंडियन एक्सप्रेस, १४ & १६७३)।

जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय ६ में विस्तारपूर्वक 'यायाधीश' हेगडे और यायाधीश राय के फैसलों के उद्धरण से स्पष्ट है, जहाँ दोनों 'यायाधीश'

सविधान और कानूना के प्रति अपनी वफादारी की शपथ का पालन करने में ईमानदार से अधिक ही बुद्धि है, वहाँ उन दानों के बीच इस बात पर बुनियादी मतभेद है कि सविधान का ठीक ठीक दर्शन क्या है। हगड के अनुसार सप्त अपने २/३ बहुमत से भी जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति करती नहीं मानी जा सकती। राय का दृष्टिकोण इसका ठीक उल्टा है।

हगडे के लिए अधिग्रहीत सम्पत्ति के प्रतिकर (मुजावजे) का प्रश्न अभी भी 'उस राशि' को निश्चित करने में अपनाया गया सिद्धान्त की तार्किक संगति के मामले का लेकर 'यायिक पुनरीक्षण' का प्रश्न हो सकता है, राय का मत है कि यह मामला वैधानिक नीति का है और 'यायिक पुनरीक्षण' की परिधि के बाहर है।

हगडे समझते हैं कि अनुच्छेद ३१ ग द्वारा जिस प्रकार निर्देशक सिद्धान्त की मूल अधिकारी से ऊपर रखा गया है, उसका जय हागा सविधान का अंत और उन्होंने यह दृष्टावली इस्तमाल की है कि, 'यह सविधान स पूरी तरह घुमेल है।' राय का मत है कि कोई निर्देशक सिद्धान्त मूल अधिकारी से ऊपर रखा जाना चाहिए या नहीं यह मामला वैधानिक नीति और विवेक का है तथा ऐसा मामला है जिसका फैसला संसद की ही करना चाहिए।

इस प्रकार यहाँ प्रश्न शासक पार्टी के दर्शन का ध्यान रखने का नहीं है बल्कि स्वयं 'यायाधीश' के अभिगम का ध्यान रखने का प्रश्न है।

रुजवल्ड ने इस दृष्टावली का इस्तमाल किया था कि वह 'यायालय' में ऐसे सदस्य नियुक्त करेंगे 'जो आधुनिक परिस्थितियों को समझते हैं' जो वैधानिक नीति पर संसद (कांग्रेस) के फैसले के विरुद्ध व्यवस्था देने का प्रयत्न नहीं करेंगे जो 'यायाधीश' की तरह काम करेंगे, कानून निर्माताओं (संसद सदस्यों) की तरह नहीं। (मार्च १९३७)।

इसलिए समस्या का सार यह है कि क्या सविधान का दर्शन वैधानिक नीति के मामले में संसद का सर्वोच्च मानन की व्यवस्था करता है या कि 'यायाधीश' स्वयं अपनी नीतियाँ को, जनता के लिए क्या भला है या क्या बुरा इसके द्वार में अपनी समझ की संसद पर लाद सकते हैं।

मोलकनाथ के मुकदमे के बाद छै बरस तक 'यायालय' में जिस बात पर संधप चलता रहा वह दरअसल इसी प्रश्न पर केन्द्रित था यानी कि एक ओर संसद और दूसरी ओर 'यायालय' के अधिकार-क्षेत्र पर। स्पष्टतः इस मामले में जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ, एक 'यायाधीश' और दूसरा 'यायाधीश' के बीच मतभेद रह है।

कोई व्यक्ति ऐसा 'यायाधीश' नहीं चाहना जो 'कायपालिका' के लिए अनुकूल बैठे, जैसा कि पालकीवाजा ने आरोप लगाया है। एक बार फिर

रुज्वेल्ट के शांति को दोहराये तो “हम ‘रीढ़हीन भगठन’ नहीं चाहते जो कानून की जवहलना करें और जो पास मामलों को उस प्रकार तै करें जैसा कि मैं उनमें तै कराना चाहता हूँ।” हम स्वतंत्र सशक्त “यायाधीश” चाहते हैं, जो हमारे सविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप अपने उच्च “यायिक अधिकार” का उपयोग करेंगे जिसके कि वे अधिकारी बनाये गये हैं। लेकिन हम ऐसे “यायाधीश” नहीं चाहते जो सविधान के दशन की अपनी समझदारी का बहाना बना कर वास्तव में कानून बनाने का काम करते हैं सविधान से ऊपर बैठते हैं—उससे नीचे नहीं। यही निष्ठापूर्ण अंतर है।

पालकीवाला ने सरकार के प्रवक्ताओं के मुँह से यह दलील दिलवायी है कि हम ऐसा मुख्य “यायाधिपति” चाहते हैं जो “संसद की परम प्रभुसत्ता और उसके असीमित अधिकारों में विश्वास रखता हो।” यह हास्यास्पद है। एक लिखित सविधान के मातहत “परम प्रभुसत्ता” का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। संसद की प्रभुसत्ता इन बातों से सीमित है (१) भूल अधिकार, (२) सविधान की अन्य व्यवस्थाओं के साथ अनुरूपता, (३) राज्या के विधानमण्डलों और संसद के बीच अधिकारों का बंटवारा।

और सरकार की ओर से कोई भी कभी संसद की परम प्रभुसत्ता के लिए नहीं झगड़ा है। किंतु हमने यह दावा जरूर किया था कि अनुच्छेद ३६८ द्वारा प्रदत्त अधिकार से सविधान को संसद, जिस तरह भी वह जनता के हितों में समझे, संशोधित कर सकती है, बशर्ते कि वह उस अनुच्छेद में निधारित क्रिया-विधि का सख्ती में पालन करे, अर्थात् संसद सदस्यों में से आधे से अधिक उपस्थिति हो और दस उपस्थित सदस्यों में से दो तिहाई संशोधन के पक्ष में वोट दें तथा कुछ अनुच्छेदों के मामले में, राज्या के विधानमण्डलों का बहुमत संशोधन का अनुमोदन करे।

स्वभावतया अधिकांश आलोचना सरकार की यह स्थिति बता कर की जाती है कि वह “बदी” या “प्रतिबद्ध यायापालिका” में विश्वास करती है, यह आरोप विरोधी दलों के नेताओं द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये स्मृतिपत्र (मैमोरेण्डम) में भी मौजूद है। यह भी सरकार की स्थिति का जानबूझ कर और सचेत रूप से तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। संसद में बोलते हुए मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम “प्रतिबद्ध यायापालिका” के समर्थक नहीं हैं, मगर हमारा विचार है कि हमें यह निश्चय करते समय कि कोई “यायाधीश” देश की सर्वोच्च अदालत का प्रधान होने के योग्य उच्चतम “यायालय” का मुख्य “यायाधिपति” होने के योग्य है या नहीं उसके दशन पर विचार करने का अधिकार है। और मैं अध्याय ६ में इस “यायालय” के दो “यायाधीशों” के मतभेदों का उदाहरण दे चुका हूँ जिनसे पता चलता है कि उनके “दशन” कितने भिन्न

है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि यायाधीश का यायापालिका की स्वतन्त्रता का प्रहरी होने का साहस हो और उसमें प्रशासनिक क्षमता भी हो। ये ऐसे तत्त्व हैं जिनका यह फैसला करने में कि कोई यायाधीश उच्च नियुक्ति के उपयुक्त है या नहीं, ध्यान अवश्य रखना चाहिए।

पालकीवाला चाहता है कि सरकार को "एसे यायाधीशों को जो शासक पार्टी के दशन का पालन करते हैं, नियुक्त करने की नीति को अविट्ट रूप में त्याग देना चाहिए।" किसी न कभी यह नहीं कहा कि सरकार एसे यायाधीश चाहती है जो पार्टी के दशन के अनुयायी हैं और यह सरकार की नीति भी नहीं है। किंतु हम यायाधीशों के दशन पर विचार करने का अधिकार है—पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि उनके कृत्यों की व्याख्या और मंत्रिमान के विषय में उनकी समझदारी के दृष्टिकोण से।

मैं इस से बहतर सिफारिश नहीं कर सकता कि पालकीवाला रुजवेट्ट का भाषण पढ़े, जिसका एक सम्भा उद्धरण इस पुस्तक के पृष्ठ ४६ पर दिया गया है। सरकार की स्थिति सत्रसे तीसरे और सुस्पष्टतम रूप में इसी में प्रकट होती है कि एक यायाधीश का दशन क्या है, इसका फैसला करते समय हमारे दिमाग में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, प्रश्न यह नहीं है कि न्यायाधीश शासक पार्टी के दशन का अनुयायी हो। यह ससद की श्रेष्ठता में विश्वास की बात है। यह जनता के प्रतिनिधि के रूप में ससद की श्रेष्ठता में और अनुच्छेद ३६८ में बतायी गयी विधि का पालन कर संविधान सहायित करने में ससद की श्रेष्ठता में जो—स्वतंत्र पार्टी और जनमत का छोड़ कर—हमारे देश में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का आस्था-सूत्र है विश्वास की बात है।

यही इस वाद विवाद का ममथल है और यह अबिक ईमानदारी तथा न्याय की बात होगी कि इस विवाद के कणधार इस तथ्य को निष्पक्षता और ईमानदारी से स्वीकार कर लें।

परिशिष्ट-१

फँसला करने में यायाधीश को जो विभिन्न तत्त्व प्रभावित करते हैं, उनका बड़ा शानदार विस्तरेण यायाधीश बार्डोजो के दो आलेख पण्डो में दिया गया है, जिनको नीचे दिया जा रहा है।

१

मैं जा विस्तरेण करने जा रहा हूँ, इस प्रयत्न में चेतन और उपचेतन में भेद करने की आवश्यकता है। मेरा यह तात्पर्य नहीं कि मैं जिन विचारों और इरादों को पहली श्रेणी में रगूंगा वे सदा चेतना में स्पष्ट रूप से उपस्थित रहते हूँ ताकि उनको पहचाना जा सके और देख कर बताया जा सके। अक्सर ही वे सनहू के आसपास मड़राते हैं। किन्तु उनको तुलनात्मक तत्परता के साथ जलन और आवद्ध किया जा सकता है तथा इस प्रकार जब उनका नामकरण कर दिया जाता है तब उनको आचार विचार का निदर्शन करने वाले सिद्धांतों के रूप में शीघ्र स्वीकार कर लिया जाता है। सनहू के बहुत नीचे जो गक्तियाँ हाती हैं वे इतनी सूक्ष्म रहती हैं कि उनको उपचेतन के अनिरिक्त जोर किसी रूप में यायपूर्वक श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। अक्सर इही उपचेतन गक्तियों के कारण यायाधीश अपने प्रति सुमगल और एक दूसरे में विसंगत रहते हैं। हमें फलवाद (फ्रैगमेंटिज्म) पर दिए गये एक व्याख्यान के महत्वपूर्ण पृष्ठ पर विलियम जेम्स स्मरण कराते हैं कि हम सब में वास्तव में एक निहित जीवन-दशन होता है—उन सब में जिन को दान के नाम और अवधारणाएँ मालूम तक नहीं हैं या जो उनको एक अभिग्राह्य समझते हैं। हम सब में एक प्रवृत्ति धारा होती है, उसे आप दान कहें या तबहें जो विचारों और क्रिया-कलापों को एक मगति और दिशा प्रदान करती है—यायाधीश भी अन्य प्राणियों की भाँति उस धारा में बच नहीं सकते। सारी जिंदगी ऐसी गक्तियाँ उनके ग्राह्य जीवन-तान करती रहती हैं जिन्हें वे पहचानते नहीं और जिनका वे नाम नहीं दे सकते—जैसे विरासत में मिली मनोवृत्ति, परम्परागत विश्वास, जीवन आस्थाएँ, और इन सबका परिणाम होता है जीवन

सम्बन्धी एक दृष्टि, सामाजिक आवश्यकताओं की एक अवधारणा, एक भावना, जिसे जेम्स के शब्दों में "ब्रह्माण्ड का सर्वांग बल प्रयोग और दबाव" कहते हैं, जो उस समय जब कि तब सुचारु रूप से सतुलित किय जाते हैं यह निर्धारित करते हैं कि चयन क्या होगा। इस मानसिक पृष्ठभूमि में प्रत्येक समस्या को अपना परिदृश्य प्राप्त होता है। हम चीजों को जितना भी मन चाहे वस्तुनिष्ठ रूप से देखने का प्रयत्न करें, तब भी उन्हें हम स्वयं अपनी आंखों के अलावा किन्हीं दूसरी आंखों से नहीं देख सकते। इसी कसौटी पर वे सब चीजें आती हैं—यकालत का कोई रूप या ससद का कोई कानून, दरिद्रों के अयाय या राजाओं के अधिकार, एक ग्रामीण अध्यापक या राष्ट्र का चाटर। (पृष्ठ ११-१२)।

२

इसलिए मेरा इस विचार से कोई झगडा नहीं है कि 'यायाधीशों को अपन समय के सकाजे के साथ हमदर्दी रखनी चाहिए। अफसोस! इस आम स्थापना की स्वीकृति भी हमें सत्य के मार्ग पर बहुत आगे नहीं ले जाती। हर 'यायालय में 'सत्य' के उतने भू-याजन होने की सम्भावना है जितने उसकी बेंच पर न्यायाधीश हों। मैं जितने 'यायाधीशों को जानता हूँ उनमें किसी भी तरह की नीचता, घुसचि और पापपूर्ण अथवा मैंन अहसान जताने या प्रवृत्ति रखने का कोई चिह्न—लेखमान चिह्न तक—नहीं पाया लेकिन हर दिन मुझे हमारे बाहर के सत्य और हमारे अंदर के सत्य के बीच ऐसे सम्बन्ध के, जिससे हम बच नहीं सकते एक नये विश्वास का बोध हुआ। युग की आत्मा का हम सबको जिस तरह बोध होता है उसमें अक्सर ही सिर्फ समूह की आत्मा हाती है जिसमें जन्म या निष्ठा या पेशा या संग साथ के समयोग से हमें स्थान मिलता है। मस्तिष्क के किसी प्रयत्न या क्रांति से इन उपचेतन वफादारियों के साम्राज्य का पूरी तरह और सदा के लिए उन्मूलन नहीं हो सकता है। जेम्स हार्वे रॉबिन्सन का कथन है, "हमारी आस्थाएँ और मत, हमारे आचरण के प्रतिमानों की तरह ही हम अनजाने ही अपने साथी इसाना के संग साथ की उपज के रूप में प्राप्त होते हैं, हमारे व्यक्तिगत अनुभव के परिणामस्वरूप नहीं, और उन निष्कर्षों से प्राप्त होते हैं जिन पर हम स्वयं अपने अवलोकन से व्यक्तिगत रूप से पहुँचते हैं। हम 'यौक्तिकीकरण' (रॉबिन्सन) की अपनी असाधारण प्रभावशालिता द्वारा लगातार

भरमाय जाते हैं—यानी कि हम जिस समूह के सदस्य होते हैं, उसकी परम्पराओं द्वारा जो कुछ हमारे ऊपर मढ़ा जाता है, उसको स्वीकार करन के लिए हम कौणलपूर्ण तब गढ़ लेते हैं। हम प्रकृति से नितात विश्वामी होते हैं और समूह के निणया को सहज-वृत्ति-वग स्वीकार कर लेते हैं। हम केवल उत्तेजित भीड़ या जोशीले पुनरुत्थान के जादुई प्रभावधर ही सुभावाग्राही नहीं हाते, बल्कि हम समूह की और भी बारीक आवाज को सदा ओर हर समय सुनते रहते हैं तथा उसकी हिमायती और चेतावनियों की हिमायत करन तथा उहे सही ठहरान के लिए सदा तैयार रहते हैं और उनको स्वयं अपनी तब प्रणाली के परिपक्व परिणाम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं।" यह बात विशेष रूप से यायाधीशों के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों के स्त्री-पुरुषों के लिए लिखी गयी थी। न्यायाधीश का प्रशिक्षण अगर उस वृत्ति से संपूर्ण हो जिसको यायिक प्रकृति कहा जाता है, तो वह उसका व्यक्तिगत अरुचियों और पूर्वधारणाओं की सुभाव शक्ति से मुक्त हाने में थाड़ी हद तक सहायता द सनती है। इससे उस समूह को विस्तृत करने में सहायता मिलेगी जिसके प्रति उसकी अचेतन वफा-दारिया अपक्षित है। जब तब मानव प्रकृति जैसी है, वैसी ही रहती है तब तक ये वफादारिया कभी पूरी तरह मिटायी नहीं जा सकती। कभी कभी हम आश्चर्य कर सकते हैं कि व्यक्तिवाद की इन सभी शक्तियों के खिलाफ स कोई सगत बात—अराजकता और शून्य के अतिरिक्त कोई और बात—कैसे पैदा हा सकती है। ये वे क्षण होते हैं जिनमें हम मित्रता के सत्वा को अतिरजित करने हैं। अतत कोई ऐसी चीज उभरती है जिसमें एक समष्टिक आकार और सत्य तथा व्यवस्था होती है। (पृ १७४)।

[बजामिन एन वार्टोओकी पुस्तक 'दि नवर आफ दि जुडीशल प्रॉसेस' से]

परिशिष्ट-२

और इसलिए यह कहना, नवनीकी दृष्टि से कितना ही सच हो, सतही बात होगी कि उदाहरणार्थ उच्चतम 'यायालय' न १९३५ में नव व्यवहार के रेलरोड अवकाश प्राप्ति जानून को जमबैधानिक घोषित कर दिया (जिमवे अतगत सभी रेल कम्पनियों को ६५ वर्ष से अधिक आयु के रेलरोड मजदूरों को पेशन अदा करने के लिए एक अनिवार्य बीमा कोष में एक वार्षिक रकम देनी पड़ती)। यह कहना अधिक सही, अधिक मायन और अधिक रहस्योद्घाटक होगा कि उच्चतम 'यायालय' के पांच 'यायाधीश' ने—जिनमें से एक ने ग्रेट नादन, नादन पैसिफिक, और गिकागो, बर्लिंगटन तथा किसी रेलरोड कम्पनियों के वकील के रूप में जो 'यायिक' प्रसिद्धि प्राप्त की, उसके कारण 'यायाधीश' पद प्राप्त किया (बटलर), एक को ऊपर की घंका देकर 'यायालय' में पढ़ाया गया था, जिसका कारण था एटर्नी जनरल के पद पर रहते हुए उसका झगड़ा रूपन जिसमें इजारेदारी घटान के अभियाग में यूयार्क, यू हेवन और हाटफोर्ड रेलरोड पर मुबदमा चलाने में उनकी हिचक भी शामिल थी (मैकरेनो-टम) एक ने सरदार के सामन और बाहर यूनियन पैसिफिक रेलरोड कम्पनी का प्रतिनिधित्व कर अपने लिए नाम कमाया और यादी दीलत भी जमा कर ली थी (वान डवटर), एक 'यायाधीश' सीनेटर हाडिंग नाम के एक सज्जन के सीनेट में मित्र थे जिन्होंने बाद में राष्ट्रपति बन जान पर उनकी 'यायालय' में नियुक्त कर लिया जब उदाह के मतदाताओं ने उनको रेलरोड कम्पनियों समेत अनेक कम्पनियों की आर से सीनेट में उनकी प्रतिक्रियावादी कारवाइया के कारण पुन निवाचित करने से इनकार कर दिया था (सदरन), तथा एक और 'यायाधीश' जेफ फिलाडेल्फिया में वकील थे तब पनसिलवानिया रेलराड कम्पनी और उसमें सम्बंधित फर्मों समेत अनेक बड़ी बड़ी कम्पनिया उनकी मुबकिन्न थी (रॉबर्ट्स), इन पांच 'यायाधीश'ों ने—अपने काफी योग्यता सहयोगियों (ट्रूजेस, ब्राडेइम, कार्डोडो, और स्टोन जिन्होंने जमहमनि प्रकट की थी) को मानान से हरा दिया और इन प्रकार कांग्रेस (संसद) की इच्छा प्रकाशन की इच्छा और भवभावत दस की जनता की इच्छा को नकार दिया तथा साथ ही, वहहाल रिक्तुल मयोगवण, रेलराड कम्पनियों का पैमा उचा किया। अपने अथ और चरादा में यह मामला जितना मुस्पष्ट है उन स्पष्ट रूप में उच्चतम 'यायालय' के सभी सर्वेधानिक फैसला की व्याख्या करना

आसान नहीं है। मगर उनमें से किसी भी फैसले की व्याख्या या विश्लेषण या समझ, "यायादीशा के रूप के बजाय, उन इंसानों के रूप के बजाय कि जिनमें वे बने थे, किसी भी त्रिभुल सनही, कानूनी स्तर के आधार पर प्राप्त नहीं की जा सकती।

[फ्रेड रोयेल की पुस्तक 'नाइन मेन ए पारिटिशन हिस्ट्री आफ दि सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम १७६० टु १९५५" (नौ इंसान १७६० से १९५५ तक उच्चतम न्यायालय का एक राजनीतिक इतिहास) में, पृष्ठ ३०३]



परिमिष्ट-३
भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति
(१९५०-१९७३)

न्यायाधीश	सेवा की अवधि	कुल कार्य काल
१ हीरालाल कानिया	२६ १ १९४६ से ६ ११-१९५१	१ वष ६ महीने और १२ दिन
२ पतञ्जलि शास्त्री	७ ११ १९५१ से ३ १ १९५४	२ वष १ महीना और २७ दिन
३ मेहरचंद महाजन	४ १ १९५४ से २२ १२-१९५४	११ महीने और २० दिन
४ विजय कुमार मुगर्जी	२३ १२ १९५४ से १ २ १९५६	१ वष १ महीना और १० दिन
५ मुधि रजन दास	१ २ १९५६ से १ ६-१९५६	३ वष ७ महीने और १ दिन
६ भुवनश्वर प्रसाद मिह्रा	१ ६ १९५६ से ३१ १ १९६४	४ वष और ५ महीने
७ पी वी गजेंद्रगडकर	१ २ १९६४ से १५ ३ १९६६	२ वष १ महीना और १५ दिन
८ ए के भग्वार	१६ २ १९६६ से २६ ६ १९६६	३ महीने और १८ दिन
९ के सुब्बाराव	३० ६ १९६६ से ११ ४ १९६७	६ महीने और १२ दिन
१० के एन वात्र	११ ४ १९६७ से २४-२ १९६८	१० महीने और १६ दिन
११ एम हिनायतुल्ला	२५ २ १९६८ से १६ १२ १९७०	२ वष ६ महीने और २१ दिन
१२ जे सी साह	१७ १२ १९७० से २१ १ १९७१	१ महीना और ६ दिन
१३ एम एम सीवरी	२२ १ १९७१ से २५ ४ १९७३	२ वष ३ महीने और ५ दिन
१४ ए एन राय	२६ ४ १९७३ से आज तक	

परिशिष्ट-५

इंग्लैण्ड के मुख्य न्यायाधिपति (१९०१-१९७३)

न्यायाधीश	सेवा की अवधि	कुल कार्य-काल
१ लाड एल्बरटनि	१९०१ १९१३	१२ वर्ष
२ लाड रीडिंग	१९१४ १९२०	६ वर्ष
३ ए टी नॉरिस (लाड ट्रेवियन) ^१	१९२१ १९२२	१ वर्ष
४ लाड हवट	१९२२ १९४०	१८ वर्ष
५ वाइकाउट कार्मेकोट	१९४१ १९४५	४ वर्ष
६ लाड गोडड	१९४६-१९५८	१२ वर्ष
७ लॉड पाकर	१९५९ १९७१	१२ वर्ष
८ लाड विहग्रे	१९७१ से आज तक	

१ लार्ड ट्रेवियन के लघु कार्य राज का वारण १९८३ पर दिया गया है

परिशिष्ट-६

कनाडा के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति
(१९००-१९७३)

न्यायाधीश	सेवा की अवधि	कुल कार्य-काल
१ सर हेनरी स्ट्रांग	-१९०२	—
२ सर हेनरी एलजीयर तादलेरिया	१९०२ १९०६	४ वर्ष
३ चार्ल्स फिटजपेट्रिक	१९०६ १९१९	१३ वर्ष
४ सर लुई हेनरी डेविस	१९२० १९२४	४ वर्ष
५ सर फ्रांसिस अलेक्जेंडर एंगलिन	१९२५ १९३३	८ वर्ष
६ राइट आनरेबल लिमन मूर डफ	१९३४ १९४४	१० वर्ष
७ थिर्वांड्यू रिनफ्रेट	१९४५ १९५५	१० वर्ष
८ पैट्रिक केरविन	१९५६-१९६३	७ वर्ष
९ राबर्ट तादलेरियो पी सी	१९६४ १९६७	३ वर्ष
१० जान रॉबर्ट काटराइट	१९६८ से आज तक	

आस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति (१९०३-१९७३)

न्यायाधीश	सेवा की अवधि	न्यायालय में आयु	राज्य	विधवा राजनीतिक अनुभव
१ प्रिफिय, मु 'या	१९०३ १९१९	५८ ७४	क्वींसलैण्ड	उपनिवेशी और राज्य स्थिति में के देश के रूप में एम एल ए ^१ मंत्री मुख्य न्यायाधिपति राजपाल एम एल ए एम एल ए मंत्री एम एच आर ^२ मंत्री एम एच आर मंत्री एम एच आर मंत्री
२ नॉक्स, मु 'या	१९१९ ३०	५५ ६६	यू साउथ वेल्स	एम एल ए
३ जाइजक्स, 'या और मु 'या	१९०६ ३० (मु 'या १९३०)	५१ ७५	विक्टोरिया	एम एल ए मंत्री
४ गावन डग्वी, 'या और मु 'या	१९१३ ३६ (मु 'या १९३१)	६१ ८४	विक्टोरिया	—
५ लयम, मु 'या	१९३५ ५२	५८ ७५	विक्टोरिया	—
६ डिकसन, 'या और मु 'या	१९२९ ६४ (मु 'या १९५२)	४३ ७७	विक्टोरिया	—
७ वारविक, मु 'या	१९६४	६०	यू साउथ वेल्स	—

१ एम एल ए—विगत सभा के सदस्य (राज्य विधान सभा में)

२ एम एच आर—हाउम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (राष्ट्रमण्डल ससद) के सदस्य

